04 - व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आधार हो बारहवीं की परीक्षा

05 - जागरूकता से आगे बढ़कर स्थायी समाधान की जरूरत

A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 16 मई, 2026

06 - 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर आशा, उषा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक...

07 - वैज्ञानिक भंडारण से गरीबों तक राशन पहुंचाने की पूरी...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 223, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

महंगा सोना : क्या भारतीय वाकई कम कर देंगे खरीदारी?

रजनीश कुमार

भारत ने सोने और चांदी पर इम्पोर्ट टैरिफ़ यानी आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15% कर दिया है। तीन फ़ीसदी जीएसटी को शामिल करने पर कुल आयात शुल्क 9.18% से बढ़कर 18.45% हो जाएगा। यानी पहले 100 रुपए का आयातित सोना क़रीब 9.18 रुपये के टैक्स के साथ भारत आता था। अब उसी आयात पर लगभग 18.45 रुपये का टैक्स लगेगा। यानी प्रभावी आयात शुल्क का बोझ 100% से अधिक बढ़ गया है।

यह क़दम ऐसे समय में उठाया गया है, जब क़ीमती धातुओं का आयात तेज़ी से बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने लगभग 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक था। वहीं चांदी का आयात 12 अरब डॉलर से अधिक का रहा था, जिसमें सालाना 150% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई।

दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) का मानना है कि यह वृद्धि भारत-यूएई कॉम्परहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीइपीए) के तहत वहाँ से आने वाले कीमती धातु आयात के गणित को भी काफ़ी बदल देगी। सीइपीए के तहत भारत ने मई 2022 से शुरू होकर 10 सालों में चांदी पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर शून्य करने पर सहमति दी थी। वर्तमान में यूएई से आने वाली चांदी पर रियायती शुल्क सात फ़ीसदी है।

अब भारत ने सामान्य आयात शुल्क को 15% कर दिया है, ऐसे में शुल्क का अंतर आठ प्रतिशत तक बढ़ गया है। इससे दुबई के जरिए आयात करना सस्ता हो गया है। जीटीआरआई के निदेशक अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि यह अंतर हर साल और बढ़ेगा क्योंकि सीईपीए के तहत टैरिफ़ 2031 तक घटकर शून्य हो जाएगा। यूएई से सोने के आयात को भी समझौते के तहत ख़ास रियायत हासिल है। भारत ने टैरिफ रेट कोटा प्रणाली के तहत दुबई से सोने के आयात पर मोस्ट-फेवर्ड-नेशन की दर से एक प्रतिशत कम शुल्क की अनुमति दी थी। यह कोटा 2022 में 120 टन प्रतिवर्ष से शुरू हुआ था और 2027 तक बढ़कर 200 टन हो जाएगा, जो भारत के वार्षिक सोना आयात का लगभग एक-चौथाई है। नई एमएफएन शुल्क व्यवस्था के तहत जहां सामान्य प्रभावी शुल्क 15% हो गया है, वहीं यूएई कोटा के तहत आने वाला सोना 14% शुल्क पर आएगा। 'आयात शुल्क के बढ़ते अंतर से वैश्विक बुलियन व्यापार का बड़ा हिस्सा दुबई के ज़रिए आने की संभावना बढ़ सकती है, जबकि यूएई ख़ुद सोना या चांदी का खनन करने वाला देश नहीं है।'

'यूएई के साथ जो समझौता हुआ है, उसमें लिखा है कि जो भी भारत का टैरिफ़ होगा, उससे एक प्रतिशत कम में दुबई से सोना आएगा। यानी बाक़ी देशों से सोना लाने पर 15 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगेगा लेकिन दुबई से लाने पर 14 प्रतिशत का ही टैरिफ़ लगेगा। सोना इतना महंगा हो गया है कि एक फ़ीसदी टैरिफ़ कम होना भी बड़ी रियायत होगी। ऐसे में दुबई से सोना लेने की होड़ लग सकती है।'

चाँदी के मामले में अजय श्रीवास्तव कहते हैं, 'सिल्वर में तो और ज़्यादा क़ीमतों में फ़र्क़ होगा। सरकार ने 15 फ़ीसदी टैरिफ़ सिल्वर के ऊपर लगाया है। लेकिन दुबई से सिल्वर के लिए कहा है कि 2031 तक ज़ीरो पर्सेंट टैरिफ़ होगा। टैरिफ़ कम होते-होते आज की तारीख़ में सात फ़ीसदी रह गया है। यानी 15 प्रतिशत बाक़ी देशों से टैरिफ़ और दुबई से केवल सात प्रतिशत। यानी आठ प्रतिशत टैरिफ़ की छूट मिलेगी। भारतीय दुबई से सिल्वर ख़रीदना पसंद करेंगे। भारत यूएई से किसी एग्रीमेंट से अचानक बाहर नहीं सकता है।'

मोदी सरकार ने आयात शुल्क में बढ़ोतरी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बुलियन बाज़ार भारत में मांग कम करने के उद्देश्य से की है। यह क़दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से सोना ख़रीदने और ग़ैर-ज़रूरी विदेशी यात्राओं से बचने को कहा था ताकि रुपये को सहारा दिया जा सके।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत, पर्शियन गल्फ़ में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से महंगाई की चपेट में है। सोना भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। बचत, विवाह और धार्मिक त्योहारों में इसकी अहम भूमिका है। भारत सोने की मांग आयात से पूरी करता है और पिछले साल 710 टन सोने का आयात हुआ था।

ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास अभी 690 अरब डॉलर का फ़ॉरेक्स है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कच्चे तेल के आयात के लिए 174 अरब डॉलर ख़र्च किए थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर 116 अरब डॉलर। तीसरे नंबर पर सोने का आयात था और जिसकी क़ीमत 72 अरब डॉलर थी। बढ़ते आयात बिलों के कारण विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ा है। इससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और भारतीय रिज़र्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा।

कंसल्टेंसी फर्म मेटल्स फोकस के प्रमुख सलाहकार चिराग शेठ ने कहा कि शादियों के लिए सोना ख़रीदना सरकारी फ़ैसले के बावजूद जारी रहेगा। इस अवधि में लोग क़ीमतें स्थिर होने का इंतज़ार करते हुए सोना ख़रीदना रोक सकते हैं।'

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर रहे अरुण कुमार कहते हैं कि 'जब रुपया कमज़ोर रहेगा तो लोग निवेश के लिए सोना ही ख़रीदेंगे। आयात शुल्क बढ़ाने का सीधा फ़ायदा यूएई को होगा और सोने की तस्करी भी बढ़ेगी।

ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल का मानना है कि सरकार ने गोल्ड पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी डॉलर बचाने के लिए नहीं बल्कि टैरिफ़ से पैसे कमाने के लिए की है। सिंघल कहते हैं, '2023 में भारत ने 743 टन सोने का आयात किया था और तब टैरिफ़ 15 फ़ीसदी ही था। पिछले साल गोल्ड पर टैरिफ़ छह प्रतिशत था और आयात 710 टन था। ऐसे में कोई कैसे मान ले कि आयात शुल्क बढ़ जाने से सोने का आयात कम हो जाएगा।'

एक मई तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.7 अरब डॉलर रह गया है, जो एक महीने से अधिक समय का सबसे निचला स्तर है। हालांकि यह भंडार अब भी 10 से 11 महीनों के आयात बिल को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

भारत के प्रमुख अंग्रेज़ी अख़बार इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम ने जब सोने की ख़रीद एक साल तक नहीं करने की अपील की उसके बाद पूरे भारत में लोगों ने घबराहट में ख़रीदारी शुरू कर दी। पिछले दो दिनों में शादी के गहनों की बिक्री औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 15% से 20% बढ़ गई है। '

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित रिपोर्ट के संपादित अंश)

धार भोजशाला को हाई कोर्ट ने मां वाग्देवी का मंदिर माना

हिंदू पक्ष की मांगें स्वीकार, हाई कोर्ट का फैसला

इंदौर। भोजशाला को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद में शुक्रवार को बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप देवी वाग्देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में स्थापित होता है। अदालत ने यह भी माना कि इस स्थान पर हिंदू समाज की पूजा-अर्चना की परंपरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा केंद्र रहा है, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता था। न्यायालय ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका का निराकरण करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर तथा संस्कृत शिक्षण से जुड़े प्रबंधन और संचालन को लेकर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने यह कहा– न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का विवादित परिसर 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक की श्रेणी में है और यह 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्र माना जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसर का समग्र प्रशासन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन ही रहेगा। फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार और पुरातत्व विभाग भोजशाला मंदिर के संरक्षण, संस्कृत शिक्षा और व्यवस्थापन को लेकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि उपलब्ध प्रमाण इस स्थान के मूल स्वरूप को मंदिर से जोड़ते हैं।

कैसे शुरू हुआ मामला

भोजशाला को लेकर विवाद लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच चला आ रहा है। हिंदू समाज का दावा है कि यह स्थल मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता रहा है। विशेष रूप से वसंत पंचमी के अवसर पर पूजा-अर्चना और नमाज को लेकर यहां कई बार तनाव की स्थिति बनती रही। यह कानूनी लड़ाई वर्ष 2022 में उस समय नए दौर में पहुंची जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की। इसके बाद मामले में लगातार सुनवाई हुई।

सर्वे में क्या मिला– मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया था। करीब 98 दिनों तक चले सर्वेक्षण के बाद 15 जुलाई 2024 को विस्तृत प्रतिवेदन अदालत में प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि परिसर में 106 स्तंभ और 82 स्थापत्य अवशेष मिले, जिन्हें पुराने मंदिरों का हिस्सा माना गया और बाद में मस्जिद निर्माण में उपयोग किए जाने की बात कही गई। कई स्तंभों पर देवी-देवताओं, शेर और हाथियों की आकृतियां मिलीं, जिनके क्षतिग्रस्त होने के संकेत भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए। जांच में 10वीं और 11वीं शताब्दी के परमारकालीन शिलालेख तथा बाद के काल के सिक्के भी मिले। दो हजार से अधिक पन्नों की रिपोर्ट में इस स्थल के मूल रूप से हिंदू मंदिर होने की संभावना व्यक्त की गई।

हिंदू पक्ष की प्रमुख मांगें– याचिका में हिंदू समाज को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार देने की मांग की गई थी। इसके अलावा परिसर में नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने, केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाकर प्रबंधन संभालने तथा मां सरस्वती की प्रतिमा की निरंतर पूजा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। याचिका में यह मांग भी शामिल थी कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाकर भोजशाला में स्थापित किया जाए।

फैसले से पहले कड़ी चौकसी

फैसले को देखते हुए धार जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने धारा 163 लागू कर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी थी। किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया। पुलिस ने सामाजिक माध्यमों पर भड़काऊ टिप्पणियों की निगरानी तेज कर दी थी। साथ ही पेट्रोल और डीजल की बोतलों में बिक्री पर भी विशेष नजर रखी जा रही थी।

वसंत पंचमी पर भी बड़ा आदेश

इस मामले में पहले भी महत्वपूर्ण आदेश सामने आ चुके हैं। 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा-अर्चना की अनुमति दी थी। इसके बाद 6 अप्रैल 2026 से इंदौर खंडपीठ में लगातार सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली। अदालत ने उसी दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार 15 मई को सुनाया गया।

मुस्लिमों को नमाज का अधिकार नहीं

हाई कोर्ट ने एएसआई का 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताते रहे मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने सरकार से मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने को कहा है।

मुस्लिम और जैन पक्ष जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और शोभा मेनन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। अब फैसले की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहीं जैन समाज की ओर से पैरवी कर रहीं एडवोकेट प्रीति जैन ने कहा कि सुनवाई के दौरान यह दावा किया गया था कि तीर्थंकरों की मूर्तियों के अवशेष आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं और उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जैन समाज भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर

भोजशाला विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह विशेन की ओर से अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने कैविएट दाखिल की। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर किसी भी अपील पर हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

गुरुदेव के आशीर्वाद से ही सनातन और सत्य मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा मिलती है: मुख्यमंत्री

जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में सिंहस्थ जैसा नजारा, स्व अनुशासन से अनुशासित लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब

उज्जैन/भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में जय गुरुदेव आश्रम में गुरुदेव महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया और उनके अमृत प्रवचनों का श्रवण किया। गुरुदेव श्री उमाकांत जी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा ऐसे ही समाज की सेवा में लगे रहे और सत्य, सनातन, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जन सेवा करते रहें। आज आप अपने कार्यों से जनता के प्यारे बन गए है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुदेव के निर्देश पर मंच से ही गुरुदेव के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरुदेव की उज्जैन में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरुवर को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं ईश्वर को देख लिया हो, यह आश्रम परमात्मा का घर है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि हमें गुरुवर का आशीर्वाद उनके स्वरूप में मिल रहा है और जीवन में सत्य कार्य करने का जो मार्गदर्शन हमें गुरुवर के चरणों से मिलता है उसे जीवन जीने का नया मार्ग हमें प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाराज जी का आशीर्वाद चिर काल तक हम सभी को मिलता रहे और आनंद के साथ जीवन का यापन करें।

सनातन धर्म में मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मानव जीवन मिलता है। इस मानव जीवन को सही तरीके से जीने का जो मार्ग आपके द्वारा बताया जाता है उससे जीवन सरल और संयमित होकर जीने का मार्ग मिल जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा की महाराज जी की कृपा से हमने प्रदेश में गौशालाओं को बनाने और संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।

उज्जैन सहित अन्य धार्मिक नगरों में भी शराब बंदी के लागू की है और प्रदेश में उज्जैन ओंकारेश्वर, महेश्वर दतिया, पीतांबरा पीठ, सलकनपुर, ओरछा, चित्रकूट सहित 19 नगर में शराबबंदी का आदेश भगवत कृपा से ही हो पाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 में उज्जैन को हम मेट्रो सिटी के साथ-साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी स्थापित कर पाएंगे। उज्जैन अब धार्मिक नगरी के साथ उत्सव की नगरी भी हो गई है गुरुदेव की कृपा से अब हम हर जिले में गीता भवन बना रहे हैं, जहां पर भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों का वाचन और आध्यात्मिक अध्ययन भी हो सकेगा। भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायी होते हुए हम सब गोपालन को भी अपना रहे हैं और गोपालक परिवारों को आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं।

शरद की सुबह

ख़तरे के भी निशान से आगे निकल गया
दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया

जुगनू को इक फ़क़ीर की ऐसी दुआ लगी
सूरज के ख़ानदान से आगे निकल गया

तंक़ीद करने वाले बहुत पीछे रह गए
मैं उनके दरमियान से आगे निकल गया

दुनिया लगी हुई है इसी छान–बीन में
मैं कैसे आसमान से आगे निकल गया

दिल टूटने के बाद तिरा ख़ानुमा ख़राब
परियों की दास्तान से आगे निकल गया

संदल तुम्हारे लम्स का महका जो एक शाम
ख़ुशबू में ज़ाफ़रान से आगे निकल गया

उर्दू ने शोहरतों को मेरी पर लगा दिए
मैं मादरी ज़ुबान से आगे निकल गया।

– शाहिद अंजुम

पेट्रोल-डीजल 3-3 रुपए महंगे हुए, नई कीमतें लागू

● दिल्ली में पेट्रोल 97.77 लीटर हुआ, कंपनियों को अभी भी 25-30 रू. प्रति लीटर का घाटा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है।

इनके बढ़ सकते हैं दाम

- मालभाड़ा बढ़ेगा
- खेती की लागत बढ़ेगी
- बस-ऑटो का किराया बढ़ेगा।

2024 से दाम नहीं बदले थे, चुनाव से पहले कटौती हुई थी– देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई थीं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में 2 प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी।

- **बढ़ी कीमतों पर भड़के राहुल गांधी, बोले– गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी–** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को कहा कि गलती मोदी सरकार करेगी और कीमत जनता चुकाएगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि तीन रुपये का झटका आ चुका, बाकी वसूली क़िस्तों में की जाएगी।
- **पेट्रोल-डीजल कीमतों में वृद्धि, कांग्रेस बोली–** चुनाव खत्म, वसूली शुरू, अखिलेश बोले साइकिल ही विकल्प पेट्रोल, डीजल में 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच आम लोगों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। इस बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है।

चांदी एक दिन में 19,693, सोना 3,000 रू. सस्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोने-चांदी की कीमतों में 15 मई को गिरावट देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी 19,693 रुपए घटकर 2.68 लाख रुपए रह गई, जो गुरुवार को 2.87 लाख रुपए पर थी।

- **डॉलर के मुकाबले रुपया 96.14 पर आया, यह ऑलटाइम लो, महंगाई बढ़ने का खतरा–** रुपया आज 15 मई को डॉलर के मुकाबले 50 पैसे गिरकर पहली बार 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। इससे पहले गुरुवार को रुपया 95.64 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा था। पिछले कुछ दिनों से रुपए में लगातार गिरावट जारी है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 16 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अस्पताल परिसर के निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने संजय गांधी अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर रीवा में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन मातृत्व एवं शिशु विंग, सहित कैंसर यूनिट व डॉक्टर्स क्वार्टस के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता कार्य करते हुए समय सीमा में कार्यों के पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान डीन डॉ. सुनील अग्रवाल उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री ने रीवा शहर के तीन एसटीपी का किया लोकार्पण,जयंती कुंज एसटीपी का होगा जीर्णोद्धार

सुंदर, स्वच्छ व स्वस्थ रीवा बनाने के लिये सभी कार्य प्राथमिकता से कराये जा रहे हैं : उप मुख्यमंत्री

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि किसी भी शहर आदर्श शहर बनाने के लिये आवश्यक है कि हर घर में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो तथा घर के कचरे व गंदे पानी का निष्पादन किया जाय। रीवा को सुंदर, स्वच्छ व स्वस्थ शहर बनाने के सभी कार्य प्राथमिकता से कराये जा रहे हैं। रीवा के हर घर में मीठा पानी पहुंचाना व घर से निकलने वाले गंदे पानी का निष्पादन करके रीवा आदर्श शहर के मानक को पूरा करेगा। उप मुख्यमंत्री ने रीवा शहर के विकास और स्वच्छता को नई दिशा देने के उद्देश्य से तीन एसटीपी का लोकार्पण किया तथा जयंती कुंज के एसटीपी के जीर्णोद्धार कार्य का भूमिपूजन किया।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जब रीवा छोटा शहर था तब यहाँ की आधी आबादी को खारा पानी मिलता था। रीवा शहर में भूमिगत नालियाँ नही थी। मगर प्रधानमंत्री जी के संकल्प व मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रीवा में हर घर को मीठा पानी दिलाने के लिये 12 टंकियाँ बन रही हैं। भूमिगत नालियाँ बनाई गई हैं तथा घरों से निकलने वाले गंदे पानी को सीवरेज प्लांट तक ले जाकर साफ करने का कार्य कराया जा रहा है। रीवा शहर के आगामी 35 वर्ष के विस्तार व आबादी के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर कार्य किये जा रहे हैं ताकि आने वाले

वर्षों में किसी भी प्रकार की समस्या न आये। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास व जनोन्मुखी कार्यों को पूरा करना चुनौती है। इसे पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराया जायेगा और रीवा के नागरिकों को महानगर की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बाबाघाट, विवेकानंद एवं बिछिया के एसटीपी के बन जाने से लगभग 25 हजार घरों का गंदा पानी साफ होगा। जयंती कुंज में पूर्व में निर्मित एसटीपी जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था उसे भी सुधारा जायेगा। शीघ्र ही एजी कालेज के समीप निर्माणाधीन एसटीपी का भी लोकार्पण होगा और संपूर्ण रीवा शहर के घरों का गंदा पानी स्वच्छ होगा तथा रीवा गंदगी मुक्त साफ शहर होगा। साथ ही बीहर नदी भी साफ व स्वच्छ होगी।

इस अवसर पर सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि बीहर नदी में गिरने वाले नालों का पानी अब साफ होकर नदी में जायेगा जिससे नदी साफ होगी व घरों का गंदा पानी भी नहीं बहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के हर घर को शुद्ध पानी दिलाने व गंदे पानी को साफ करने के संकल्प को उप मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपेक्षा की कि रीवा को स्वच्छता में 7 स्टार दिलाने में सहयोग करें ताकि हमारा रीवा भी देश के साफ शहरों की सूची में और ऊपर आ जाय।

संक्षिप्त समाचार

● बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

राम मंदिर निर्माण में हमेशा बाधा बनते रहे सपा, बसपा और कांग्रेस

महराजगंज (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की प्रक्रिया बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके व बिना झुके चलती रहेगी। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम जैसे ऐतिहासिक कार्य संभव हुए।सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इन कार्यों में हमेशा बाधा बनती रहीं। इसी बाधा को पश्चिम बंगाल की जनता ने हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को महराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ की लागत से 79 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास तथा लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं टूलकिट वितरित करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित रह रहे थे ।

सीएम योगी ने गन्ना मूल्य भुगतान,3.21 लाख करोड़ सीधे बैंक खातों में भेजे, 36000 करोड़ का कर्ज माफ किया– उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 3,21,963 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करके इतिहास रचा है। यहां जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। अपने पहले फैसले में किसानों की 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर्जमाफी करने वाली सरकार के निर्देश पर किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा रहा है

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का आरजी कर, रेप और मर्डर केस में बड़ा एक्शन, पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत तीन आईपीएस अधिकारी सस्पेंड

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बहुचर्चित आरजी कर कांड में शुक्रवार को अब तक की सबसे बड़ी कारवाई की है।राज्य सचिवालय नवान्न में दोपहर में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों विनीत गोयल (कोलकाता पुलिस के तत्कालीन पुलिस आयुक्त), इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता के निलंबन की घोषणा की। सुवेंदु ने तीनों आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।

ट्रक ने चाचा-भतीजे को 100 मीटर घसीटा, सिर-धड़ से अलग

झांसी में बीच सड़क टुकड़ों में बिखरी लाश, दो दिन पहले ही शादी तय हुई थी

झांसी (एजेंसी)। झांसी में शुक्रवार को बेकाबू ट्रक ने चाचा-भतीजे को रौंद दिया। दोनों बाजार से सब्जी खरीदकर बाइक

से घर लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। भागने की कोशिश कर रहे ट्रक ने दोनों को लगभग 100 मीटर तक घसीटा। इससे चाचा के शव के कई टुकड़े हो गए और सिर भी धड़ से अलग हो गया। हादसा शुक्रवार को झांसी-कानपुर हाइवे पर चिरगांव थाना क्षेत्र में बाईपास पर हुआ है।

भारत करवा सकता है ईरान-अमेरिका में समझौता

● नई दिल्ली में बोले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

नई दिल्ली (एजेंसी)। मिडिल ईस्ट संकट और ईरान-अमेरिका टकराव के बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत अपनी मजबूत

कूटनीतिक छवि, संतुलित विदेश नीति और ब्रिक्स अध्यक्ष होने के नाते ईरान, अमेरिका और अरब देशों के बीच संवाद कायम कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव, तेल आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है।

मप्र की भाजपा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजाक बना दिया है : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रशासनिक अराजकता, शिक्षकों के साथ अन्याय और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। सरकार को यह तक नहीं पता कि लाखों कर्मचारी किस विभाग के अंतर्गत आते हैं और उनकी पेंशन की जिम्मेदारी किसकी है।

श्री पटवारी ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 3 लाख शिक्षकों को अपना कर्मचारी मानने से इंकार किया जाना बेहद गंभीर और अमानवीय मामला है। इस निर्णय के कारण लाखों शिक्षकों की पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा और लगभग 20 वर्षों की वरिष्ठता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों पर सीधा हमला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था एक क्रूर मज़ाक बन चुकी है। जो शिक्षक वर्षों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, आज वही अपने भविष्य और अधिकारों को लेकर

असुरक्षित हैं। सरकार को तत्काल स्पष्ट करना चाहिए कि इन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, पेंशन और वरिष्ठता की जिम्मेदारी कौन लेगा।

श्री पटवारी ने कहा कि एक ओर प्रदेश के लाखों युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार नौकरियां समाप्त कर रही है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर 25 लाख से अधिक युवक-युवतियों ने पंजीकरण कराया है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में बेरोजगारी भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है। श्री पटवारी ने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय सरकार ने प्रदेश में 1.2 लाख से अधिक पद समाप्त कर दिए। सरकार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है कि उसके पास वेतन देने के लिए बजट नहीं है। यदि सरकार के पास कर्मचारियों और युवाओं के लिए बजट नहीं है, तो फिर हजारों करोड़ रुपये के कर्ज लेकर इवेंटबाज़ी और प्रचार पर खर्च कैसे किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के तथाकथित रोजगार मेले केवल दिखावा और प्रचार का माध्यम बन चुके हैं। एक लाख से अधिक पद समाप्त कर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उसे प्रदेश के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय प्रदेश को बेरोजगारी की ओर धकेल रही है।

श्री पटवारी ने मांग की कि सरकार तत्काल शिक्षकों से जुड़े फैसले को वापस ले और सभी शिक्षकों को नियमानुसार पेंशन, सेवा सुरक्षा एवं वरिष्ठता का लाभ सुनिश्चित करे। साथ ही समाप्त किए गए पदों को पुनः बहाल कर नए पद सृजित किए जाएं ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम

● जज कार पूलिंग करके कोर्ट जाएंगे मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर फैसला

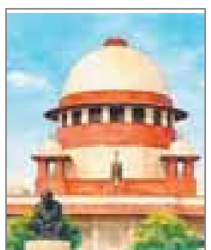

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोर्ट के हर विभाग का स्टाफ दो दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। सभी जज कार पूल करेंगे। रजिस्ट्री से जुड़ा 50 फीसदी स्टाफ भी घर से काम करेगा। सोमवार, शुक्रवार और मिसलेनियस डे (जो दिन पहले से तय नहीं होते) पर लिस्ट मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा कोर्ट के अन्य वर्किंग डे में भी सुनवाई ऑनलाइन ही की जाएगी।

भदोही-संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पत्नी व बेटे को 10-10 साल कैद; बहू को चार साल की सजा

सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत उनकी पत्नी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा को कोर्ट ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं उनकी बहू रूपा मिश्रा को चार साल कैद की सजा मिली है। एमपीएमएलए की अदालत ने संपत्ति हड़पने के मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। पूर्व विधायक की पत्नी और उनकी बहू को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ही सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गुजरात की लोक-डायरो परंपरा, नोटों के ढेर से ढंक गया भजन गायक

बोरे में भरकर लाए गए थे, पूरा पैसा दान होगा

जूनागढ़ (एजेंसी)। गुजरात के जूनागढ़ जिले के खंभालिया गांव में श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। इसी दौरान हुए लोक डायरो (भजन कार्यक्रम) में लोक गायक जिग्नेश कविराज के ऊपर जमकर नोट बरसे। भजन कार्यक्रम अहीर समाज और प्रयागराज समूह द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान भक्तों ने गायक पर करीब डेढ़ घंटे तक रूपयों को बरसात की। कुछ लोग बोरियों में नोट भरकर लाए थे। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

कन्या स्कूल के लिए दी जाएगी दान राशि- अहीर समाज के आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7 दिनों में जो भी दान राशि मिली है। वह अहमदाबाद में बन रहे 'गुजरात अहीर समाज कन्या कक्षालय' के निर्माण में दान की जाएगी। बेटियों की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही लोगों ने जमकर दान दिया है।

दिल्ली में पहली बार दौड़ीं हाइड्रोजन बसें, इन सुविधाओं से हैं लैस

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में पहली बार हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू हो गया है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ मिलकर आज दिल्ली के सेंट्रल विस्टा एरिया में एक इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन-पावर्ड शटल बस सर्विस शुरू की है। 15 मई शुक्रवार सुबह 8:30 बजे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से पैसेंजर सर्विस के लिए दो हाइड्रोजन बसें शुरू की गईं। इन बसों की चाबियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर (रिफाइनरी), अरविंद कुमार ने डीएमआरसी और आईएसीएल के दूसरे सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में डीएमआरसी के डायरेक्टर (ऑपरेशंस एंड सर्विसेज) डॉ. अमित कुमार जैन को सौंपीं।

● मोदी के प्लेन को एफ-16 फाइटर जेट से सुरक्षा दी गई

भारत-यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता

दुबई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे हैं। अबूधाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के एफ-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम

रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान भी किया है।

मोदी बोले-

होर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहना जरूरी- मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित बना रहे। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है और भारत हमेशा संवाद व कूटनीति के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है।

यूएई पर हमले किसी भी रूप में स्वीकार नहीं- मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे।

● नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को

● यह पेपर-पेंसिल से होगी, सरकार ने माना- पेपर लीक हुए

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी-2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे।

उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो

जाए। इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब यह परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। एनटीए ने सरकार को बताया। फिर 12 मई को रीएग्जाम का फैसला लिया गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा, 'रीएग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। छात्र रीएग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुन पाएंगे।' इससे पहले 3 मई को यह एग्जाम देश के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुई था।

● **नीट पेपर लीक केस में अब तक 7 गिरफ्तारियां-** सीबीआई ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 यानी राजस्थान से पकड़े गए मांगी लाल बिंवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिंवाल, बेटा विकास बिंवाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है।

पंजाब के किसानों का चंडीगढ़ कूच, पुलिस से भिड़े

● ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें छोड़ी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब के किसानों ने 15 मई को चंडीगढ़ कूच किया। किसान विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने जा रहे थे। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान मोहाली के बायपीएस चौक पर

जुटे, जहां से उनका चंडीगढ़ की ओर बढ़ने का कार्यक्रम था। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट पर रही। पुलिस ने बायपीएस चौक से चंडीगढ़ जाने वाले मुख्य रास्ते को सील कर दिया। इसके अलावा सेक्टर-50 की ओर जाने वाली सड़क पर भी भारी बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि यह रास्ता राज्यपाल के आसपास के इलाके की तरफ जाता है। इसके बावजूद किसान आगे सेक्टर-50 वाले मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे।

ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार

इंदौर। द्वारकापुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो क्षेत्र में ब्राउन शुगर की सप्लाई करने की फिराक में था। आरोपी के कब्जे से 18 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सूर्यदेव नगर के खाली मैदान में एक संदिग्ध युवक मादक पदार्थ लेकर खड़ा है। सूचना मिलते ही द्वारकापुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान रोहन पिता राजू राठौर निवासी चांदमारी ईंट भट्टा के रूप में हुई है। बरामद की गई ब्राउन शुगर की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 लाख 80 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि वह मादक पदार्थ कहां से लाया था और शहर में किन लोगों को इसकी सप्लाई करने वाला था।

मास्टर प्लान सड़कों की गुणवत्ता परखी

इंदौर। शहर के बाहरी इलाकों में बन रही मास्टर प्लान सड़कों को लेकर नगर निगम अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। गुरुवार को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने विभिन्न निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण कर एजेंसियों को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने सबसे पहले इंदौर बायपास स्थित होटल प्राइड से सिटी फॉरेस्ट तक बन रही करीब 29.52 करोड़ रुपए की सड़क का जायजा लिया। इसके बाद 22.72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे जम-जम चौराहा से स्टार चौराहा मार्ग, 8.77 करोड़ रुपए के रिंग रोड खजराना मंदिर से जम-जम चौराहा मार्ग और 8.19 करोड़ रुपए की लागत वाले सांवेर रोड पेट्रोल पंप से शिव शक्ति नगर हनुमान मंदिर मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निर्माण गुणवत्ता, कार्य प्रगति और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग, संकेतक बोर्ड, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि आमजन और वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

आरा मशीन पर वन विभाग की कार्रवाई

इंदौर। वन विभाग ने गुरुवार को अवैध रूप से संचालित आरा मशीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सांवेर सब रेंज के ग्राम टिगरिया बादशाह स्थित इस आरा मशीन को सील कर दिया। वन विभाग को शिकायत मिली थी कि संगीता निगम पति धर्मेन्द्र निगम की आरा मशीन का बिना अनुमति स्थान परिवर्तन कर संचालन किया जा रहा है। शिकायत के बाद गठित टीम मौके पर पहुंची और जांच की। जांच में पाया गया कि लाइसेंस धारी द्वारा वन विभाग से किसी प्रकार की लिखित स्वीकृति लिए बिना ही आरा मशीन का गड्डा परिवर्तन कर दिया गया था। वन अधिकारियों ने इसे मप्र काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम 1984 का उल्लंघन माना। इसके बाद मौके पर ही आरा मशीन को सील कर पीओआर प्रकरण क्रमांक 904/1 दर्ज किया गया।

बदमाशों का उत्पात, चोरी के बाद तोड़फोड़

इंदौर। शहर के सराफा थाना क्षेत्र स्थित धान गली में देर रात बदमाशों ने चोरी और तोड़फोड़ कर इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए बर्तन और अन्य सामान भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक देर रात तीन बदमाश धान गली पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने एक चाय दुकान को निशाना बनाया और वहां रखी गैस भट्टी, बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। वारदात के बाद बदमाशों ने आसपास की दुकानों के ताले तोड़ने का भी प्रयास किया। इसी दौरान संदिग्ध आवाज सुनकर क्षेत्र के रहवासी जाग गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों को अपनी ओर आता देख बदमाश घबराकर भागने लगे। भागते समय उन्होंने गली में खड़ी कई दोपहिया वाहनों को गिरा दिया, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गई। सूचना मिलते ही सराफा पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर घेराबंदी की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली है। पुलिस अब उनके तीसरे फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है।

पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में आग

इंदौर। मांगलिया क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। चालक की सतर्कता के कारण जलते टैंकर को तुरंत पंप से दूर कर दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। दमकल विभाग के अनुसार घटना सुबह करीब 10 बजे की है। अशोक लेलैंड शोरूम के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े खाली टैंकर के चालक कक्ष में अचानक आग भड़क उठी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल दल मौके पर पहुंचा और पानी की बौछार कर आग पर काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने से आग टैंकर के अन्य हिस्सों तक नहीं फैल सकी। दमकल कर्मियों ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया था, जबकि दूसरी ओर से वाहनों की आवाजाही जारी रखी गई। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों को भी तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कुछ देर तक इलाके में दहशत का माहौल बना रहा।

एक्टिवा सवार से मारपीट का वीडियो वायरल

इंदौर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तीन युवक एक एक्टिवा में तोड़फोड़ करते और चालक से विवाद करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना जवाहर मार्ग क्षेत्र की है, जहां मामूली टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि युवकों ने एक्टिवा सवार के साथ मारपीट भी की और वाहन को नुकसान पहुंचाया। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। मामले को लेकर पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है।

शराब कारोबारी की खुदकुशी मामले की जांच कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी

हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली और लापरवाही पर सवाल उठाए

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शराब कारोबारी दिनेश मकवाना की खुदकुशी मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि मामले में प्रारंभिक तौर पर अपराध दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने योग्य पर्याप्त सामग्री मौजूद थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि अब केंद्रीय एजेंसी तत्काल मामला दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच करेगी। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने यह आदेश संतोष की याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनके बेटे दिनेश मकवाना ने आबकारी विभाग की तत्कालीन सहायक आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित की कथित रिश्वत मांग और प्रताड़ना से परेशान होकर 8 नवंबर 2025 को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस निष्क्रियता पर नाराजगी

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 29 नवंबर 2025 को खुदकुशी से जुड़ा वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। अदालत ने भी पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। आदेश में कहा गया कि पुलिस ने केवल साइबर फोरेंसिक रिपोर्ट हासिल की, जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो सका कि

वीडियो संबंधित मोबाइल से ही रिकॉर्ड हुआ था या नहीं। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर वीडियो और कथित सुसाइड संदेश को खारिज नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादी अधिकारी की ओर से दलील दी गई कि वीडियो दशहरे से पहले रिकॉर्ड किया गया था, जबकि आत्महत्या नवंबर में हुई। इसलिए दोनों घटनाओं के बीच तत्काल संबंध नहीं माना जा सकता। इस पर अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम तक पहुंच चुका है, तो केवल इस कारण कि उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद जान नहीं दी, उसके आरोप अविश्वसनीय नहीं हो जाते। संभव है कि उसने बाद में अपना मन बदलने या हालात सुधारने की कोशिश की हो,

समझौते वाला वीडियो भी पेश

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में एक और वीडियो प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथित तौर पर मंदाकिनी दीक्षित एक मॉल में परिवार से समझौते की बात करती दिखाई दीं। वीडियो में मृतक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात भी कही गई थी। अदालत ने इसे भी महत्वपूर्ण सामग्री माना।

लेकिन अंततः परेशान होकर आत्महत्या कर ली हो।

मंदाकिनी दीक्षित की ओर से निजी विशेषज्ञ की एक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई, जिसमें वीडियो को संपादित और छेड़छाड़ किया हुआ बताया गया। अदालत ने कहा कि जांच के शुरुआती चरण में निजी रिपोर्ट के आधार पर वीडियो को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश दिखाई देती है और संबंधित थाना आबकारी अधिकारी के प्रभाव में काम करता नजर आया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

अदालत ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी से जांच केवल विशेष परिस्थितियों में कराई जाती है। लेकिन जब जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठें और प्रथम दृष्टया अपराध दिखाई दे, तब अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि कनाड़िया थाना तत्काल पूरा प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे। साथ ही एजेंसी को स्वतंत्र रूप से जांच कर मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रति केंद्रीय एजेंसी के अधिवक्ता को भी भेजने को कहा गया है, ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके।

वीडियो में गंभीर आरोप

अदालत के सामने पेश वीडियो में दिनेश मकवाना ने आरोप लगाया था कि देवास जिले में उसकी शराब दुकानों के तीन समूह थे और आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित हर दुकान से डेढ़ लाख रुपये प्रतिमाह मांग रही थीं। वीडियो में यह भी कहा गया कि प्रति बोतल 10 रुपये कमीशन मांगा जाता था और अब तक 20 से 22 लाख रुपये दिए जा चुके थे। दिनेश ने आरोप लगाया था कि पैसे नहीं देने पर गोदाम से शराब की आपूर्ति रुकवा दी जाती थी। लगातार दबाव और प्रताड़ना के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात वीडियो में कही थी।

घरेलू विवाद का हिंसक रूप, पिता ने बेटे व पत्नी पर चाकू से हमला किया

सोते बेटे पर वार, बचाने पहुंची पत्नी भी घायल, घटना कैमरे में कैद

इंदौर। खजराना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक घरेलू विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। एक व्यक्ति ने अपने ही बेटे और पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय साजिद खान पर उसके पिता जाहिद ने हमला किया। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी शमा भी हमले की चपेट में आ गई और घायल हो गई। परिचितों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से साजिद और उसके पिता जाहिद के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह साजिद घर में सो रहा था, तभी जाहिद ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में साजिद के पैर में गंभीर चोट आई, जबकि उसकी मां शमा के हाथ में घाव हो गया। घटना के बाद परिवार के परिचित दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जाहिद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।

सामने आया घटना का वीडियो- पूरे घटनाक्रम का कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। पुलिस ने जांच के लिए वीडियो अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की पड़ताल की जा रही है।

भर्ती परीक्षा को लेकर अस्पताल में विवाद नर्सों ने लगाया दबाव, धमकी का आरोप

परीक्षा की अनुमति न मिलने से नर्सें नाराज, प्रबंधन ने कारण बताया कि क्यों!

इंदौर। बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सों ने अस्पताल प्रबंधन पर मनमानी और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सिंग अधिकारी और सिस्टर ट्यूटर भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रही नर्सों का कहना है कि उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए अवकाश नहीं दिया जा रहा है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई और हॉस्टल खाली कराने तक की चेतावनी भी दी जा रही है। जानकारी के अनुसार अस्पताल की लगभग 30 से 35 नर्सों ने सरकारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है। परीक्षा 15 मई को आयोजित होना है और कई नर्सों के परीक्षा केंद्र भोपाल सहित दूसरे शहरों में बनाए गए हैं। ऐसे में उन्हें यात्रा और परीक्षा के लिए अवकाश की आवश्यकता है। नर्सों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया है। नर्सों के मुताबिक नर्सिंग अधीक्षक सीबी जॉर्ज की ओर से एक ध्वनि संदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 15 मई को जो कर्मचारी परीक्षा देने जाएगा, वह अपनी जिम्मेदारी पर जाएगा। अस्पताल की ड्यूटी व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। संदेश में यह भी कहा गया कि नियुक्ति के समय परीक्षा के लिए छुट्टी देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, इसलिए किसी प्रकार का समायोजन संभव नहीं है।

नर्सों में नाराजगी की वजह

इस फैसले से परीक्षा में शामिल होने वाली नर्सों में नाराजगी बढ़ गई है। कई नर्सों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना उनका अधिकार है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उन पर दबाव बनाकर परीक्षा से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यदि वे परीक्षा देने जाती हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।

नर्सों को चेतावनी दी – अस्पताल परिसर के हॉस्टल में रहने वाली नर्सों को भी सख्त संदेश भेजे जाने की बात सामने आई है। संदेश में कहा गया कि 14 और 15 मई को किसी भी कर्मचारी को रात्रि अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और हॉस्टल खाली करना पड़ सकता है।

अस्पताल प्रबंधन का पक्ष

अस्पताल के संचालक राहुल पाराशर ने मामले में कहा कि यदि एक साथ बड़ी संख्या में नर्सें अवकाश पर चली जाएगी तो अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किडनी यूनिट जैसी आपात सेवाओं में नर्सों की आवश्यकता लगातार बनी रहती है। ऐसे में मरीजों की देखभाल प्रभावित होने की आशंका है। राहुल पाराशर ने यह भी कहा कि अस्पताल ने किसी नर्स को परीक्षा देने से नहीं रोका है। प्रबंधन की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि परीक्षा में जाने वालों को नियमित अवकाश की सुविधा नहीं दी जा सकेगी।

एटीएम के बाहर युवक से पांच हजार रुपए की सरेआम ठगी

फर्जी ट्रांजेक्शन दिखाकर नकद रुपए लेकर फरार

इंदौर। पलासिया थाना क्षेत्र में एटीएम के बाहर एक युवक से ठगी का मामला सामने आया है। बदमाश ने मदद मांगने के बहाने युवक से पांच हजार रुपये नकद लिए और बदले में मोबाइल पर झूठा ऑनलाइन भुगतान दिखाकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। पूरी घटना पास की दुकान में लगे निगरानी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। जानकारी के अनुसार खजराना निवासी अमन खान बुधवार रात करीब आठ बजे चंद्रलोक कॉलोनी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर रुपये जमा करने पहुंचा था। अमन के मुताबिक उसे किश्त जमा करनी थी, इसलिए वह करीब 12 हजार रुपये लेकर गया था। इसी दौरान स्कूटर से दो युवक वहां पहुंचे। इनमें से एक युवक एटीएम के भीतर आया और अमन से कहा कि उसे किसी व्यक्ति को तुरंत पांच हजार रुपये नकद देने हैं। आरोपी ने बदले में मोबाइल से रकम भेजने की बात कही। काफी देर तक अनुरोध करने के बाद अमन ने सहायता के तौर पर उसे पांच हजार रुपये नकद दे दिए।

भुगतान होने की फर्जी जानकारी - रुपये लेने के बाद आरोपी ने अपने मोबाइल में भुगतान होने की कथित जानकारी दिखाई और तुरंत बाहर निकलकर साथी के साथ स्कूटर पर बैठकर भाग गया। काफी देर तक खाते में रकम नहीं पहुंचने पर अमन को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। इसके बाद अमन ने पास की दुकान से निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाई और शिकायत लेकर पलासिया थाने पहुंचा। बताया जा रहा है कि वह करीब आधे घंटे तक ड्यूटी अधिकारी का इंतजार करता रहा, लेकिन अधिकारी व्यस्त होने के कारण उससे मुलाकात नहीं हो सकी।

नकली मच्छर रोधी उत्पादों का धंधा उजागर हुआ, दो आरोपी गिरफ्तार

गुजरात से लाकर इंदौर में बेच रहे थे नकली हिट और गुड नाइट

इंदौर। शहर में नकली कीटनाशक और मच्छर भगाने वाले उत्पादों की बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। गुरुवार को अपराध शाखा और हीरा नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी नामी कंपनी के नकली हिट और गुड नाइट उत्पाद बाजार में बेच रहे थे। पुलिस ने उनके पास से करीब 30 हजार रुपये कीमत का नकली सामान जब्त किया है।

मामले में गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स से जुड़ी बौद्धिक संपदा सेवा इकाई के सहायक प्रबंधक सुभाष शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि महेश चौहान और हरीश चावड़ा नामक आरोपी बाजार में कंपनी के नकली उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद अपराध शाखा, हीरानगर थाना पुलिस और कीटनाशक निरीक्षक सीएल मालवीय की टीम ने दीनदयाल उपाध्याय नगर और सुखलिया क्षेत्र में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास रखी चार बोरियों की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में नकली हिट स्प्रे और गुड नाइट रिफिल पैक बरामद किए गए। जांच में पुलिस ने 70 बोतल काला हिट मच्छर रोधी स्प्रे, 26 बोतल लाल हिट कॉकरोच रोधी स्प्रे और 1450 गोदरेज गुड नाइट मच्छर रोधी रिफिल पैक जब्त किए। विशेषज्ञों की शुरुआती जांच में सभी उत्पाद नकली और निम्न गुणवत्ता के पाए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गुजरात से नकली सामान लाकर इंदौर के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई करते थे।

पानी संकट पर फूटा गुस्सा, खाली मटके लेकर सड़क पर उतरे लोग

निगम के सभी जोनल कार्यालयों पर प्रदर्शन, गुस्से में मटके फोड़े

इंदौर। शहर में गहराते पानी संकट को लेकर शुक्रवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों पर वार्डों से पहुंचे महिलाओं, बच्चों और स्थानीय रहवासियों ने खाली मटके लेकर प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इंदौर नगर निगम का बजट अब साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को नियमित रूप से पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। कई क्षेत्रों में टैंकर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है।

टैंकर व्यवस्था फेल

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्षद कुणाल सोलंकी ने कहा कि निगम की टैंकर व्यवस्था

पूरी तरह फेल साबित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक वार्ड में नियमित पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो पूरे शहर की व्यवस्था कैसे संभाली जा रही है। कांग्रेस नेताओं और रहवासियों ने निगम इंजीनियरों व अधिकारियों पर लापरवाही और पक्षपात के आरोप भी लगाए। महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर विरोध जताया और कहा कि सरकार यदि योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो आम जनता को पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी मिलनी चाहिए।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक हर वार्ड में नियमित पानी सप्लाई और टैंकर व्यवस्था सुचारु नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं निगम प्रशासन की ओर से लोगों को जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया है। सहायक यंत्री प्रवीण शर्मा ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त टैंकर भेजने और सप्लाई व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्कूल के शिविर में छात्रा से 'बेड टच' किया, शिक्षक पर आरोप

निजी स्कूल में परिजनों के हंगामे के बाद पहुंची पुलिस

इंदौर। राजेंद्र नगर क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान 13 वर्षीय छात्रा ने एक शिक्षक पर अनुचित स्पर्श करने का आरोप लगाया है। घटना सामने आने के बाद छात्रा के परिजन विद्यालय पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिसकर्मियों और महिला कर्मचारियों की उपस्थिति में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी यशवंत बड़ोले ने बताया कि गुरुवार रात विद्यालय में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। परिजनों का कहना है कि विद्यालय में 3 मई से ग्रीष्मकालीन शिविर संचालित हो रहा है। आरोप है कि विनोद नाम का शिक्षक छात्राओं के साथ अनुचित तरीके से व्यवहार करता था और गलत ढंग से स्पर्श करता था। छात्रा ने घर पहुंचकर इसकी जानकारी अपने परिवार को दी, जिसके बाद परिजन रात में विद्यालय पहुंचे और पुलिस को बुलाया गया। थाना प्रभारी के अनुसार अभी तक किसी छात्रा से विस्तृत बयान नहीं लिए जा सके हैं। पूछताछ के लिए महिला कर्मचारियों को बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि थाने में अब तक कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच जारी है।

संपादकीय

केरलम् में सतीशन पर मुहर

केरलम में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दस दिनों तक चली ऊहापोह के बाद आखिर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता वी.डी.सतीशन को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। वो राज्य के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। केरलम् में सीएम पद की दौड़ में तीन नाम थे, जिनमें अव्वल नंबर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम पद के दावेदार के.सी.वेणुगोपाल तथा तीसरे नंबर पर वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नजदीकी के चलते वेणुगोपाल सीएम बन सकते हैं, लेकिन राज्य के लोग सतीशन के पक्ष में ज्यादा थे। यही नहीं, कांग्रेसनीत यूडीएफ गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो पहले ही सतीशन के रूप में अपनी पसंद जाहिर कर दी थी। लिहाजा इसे मुस्लिम लीग के दबाव में किया गया फैसला भी माना जा सकता है। उत्तर केरल में आईयूएमएल की भूमिका अहम है, खास तौर पर वायनाड जैसी लोकसभा में और 10 से 12 विधानसभाओं में भी उनका प्रभाव है। बावजूद इसके इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि सतीशन राज्य में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और केरल की राजनीति से उनका जमीनी जुड़ाव है। अधिकांश विधायक भी उन्हीं के पक्ष में थे। पार्टी आलाकमान ने अंतिम फैसले के पहले संगठन के विभिन्न स्तरों से फीडबैक लिया और सतीशन के पक्ष में ग्रास रूट सेंटीमेंट को ज्यादा तवज्जो दी। वैसे सतीशनको कांग्रेस नेता प्रियंका और सोनिया गांधी के भी करीबी माना जाता है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कहने पर ही बनाया गया था। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो की भूमिका अहम थी। जबकि वेणुगोपाल 6 साल से केन्द्र की राजनीति में सक्रिय हैं। उनका लोकल कनेक्ट कम हो गया था। वीडी सतीशन कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जो कि 2001 में पहली बार परवूर से चुनाव जीतने के बाद इस सीट से कभी नहीं हारे। सतीशन एलएलएम तक शिक्षित हैं। उनकी अध्ययन में गहरी रूचि है। राजनीति में उन्होंने छात्र जीवन में ही केरल स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से कदम रख दिया था। और 1986-1987 के दौरान महात्मा गांधी विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी निभाई। बाद में हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। चुनावी राजनीति में उनका पहला कदम 1996 में पड़ा, जब उन्होंने परावूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यह क्षेत्र तब कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था और उन्हें भाकपा के उम्मीदवार पी. राजू से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद सतीशन ने हार नहीं मानी और क्षेत्र में सक्रिय रहे। साल 2001 में उन्हें अपनी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता मिली, जब वे परवूर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार केरल विधानसभा के लिए विधायक चुने गए और तब से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2011 से 2016 के बीच जब राज्य में यूडीएफ (यूडीएफ) की सरकार थी, तब सतीशन पार्टी के अंदर ही एक बागी आवाज के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने हरित राजनीति का समर्थन किया और अपनी ही पार्टी के नेताओं के प्रभावशाली सामुदायिक नेताओं के आगे झुकने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने हमेशा चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए योग्यता को पैमाना बनाने की वकालत की। करोड़पति नेता सतीशन के सामने आगे कई चुनौतियां हैं। उन्हें राज्य में कांग्रेस को मजबूत करना और भाजपा के बढ़ते असर को रोकना है। साथ ही केन्द्र सरकार से बेहतर तालमेल बनाते हुए केरलम् को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। सबसे पहले तो सतीशन को अपनी ही पार्टी के केसी वेणुगोपाल से निपटना होगा, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वेणु सतीशन को चैन से राज करने देंगे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आधार हो बारहवीं की परीक्षा

नजरिया

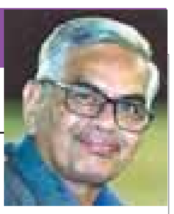

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

भारत में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं (जैसे नीट यूजी 2026) में पेपर लीक होना एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर देता है। जब पेपर लीक होता है, तो अयोग्य छात्र पैसे के दम पर सीट हासिल कर लेते हैं। इससे उन मेहनती और योग्य छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाता है जिन्होंने वर्षों तक दिन-रात मेहनत की होती है। बार-बार परीक्षाओं का रद्द होना या धांधली की खबरें आना छात्रों में डिप्रेशन, चिंता और सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा करता है। एक औसत भारतीय परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए जीवन भर की कमाई लगा देता है। परीक्षा रद्द होने पर कोचिंग, फॉर्म और यात्रा का अतिरिक्त आर्थिक बोझ माता-पिता पर पड़ता है। यदि पेपर लीक की सुविधा से बिना योग्यता वाले लोग डॉक्टर बनेंगे, तो भविष्य में देश की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिरेगा, जो सीधे तौर पर जन-स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

केवल मेडिकल परीक्षाओं में ही नहीं हमारे यहां अन्य व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं में भी ऐसी पेपर लीक हो जाने की घटनाएं होती रहीं हैं। इंजीनियरिंग, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आए पेपर लीक मामलों ने युवाओं में निराशा और आक्रोश पैदा किया है।

नीट 2024 के प्रश्नपत्र लीक होने और अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया। कई राज्यों में गिरफ्तारी हुई और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न उठे। यूजीसी नेट (GC-NET 2024) परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया क्योंकि इसके प्रश्नपत्र डार्क वेब और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने की आशंका जताई गई। Staff Selection Commission तथा रेलवे भर्ती परीक्षाओं में कई बार तकनीकी गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोप लगे। 2018 में व्यापक छात्र आंदोलन भी हुए। व्यापमं घोटाला भारत के सबसे चर्चित परीक्षा घोटालों में से एक रहा। इसमें मेडिकल प्रवेश, भर्ती परीक्षाओं और फर्जी अभ्यर्थियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस भर्ती, पटवारी परीक्षा, शिक्षक भर्ती आदि में भी कई राज्यों में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएँ सामने आईं। इससे लाखों परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा देनी पड़ी।

दरअसल, पेपर लीक अब छोटे स्तर की घटना नहीं रह गई है। इसमें कई बार कोचिंग माफिया, साइबर अपराधी, प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी, दलाल और कुछ भ्रष्ट अधिकारी शामिल पाए जाते हैं। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के कारण हमारी परीक्षा प्रणाली कमजोर और असुरक्षित हो गई है। कई बार प्रश्नपत्रों की छपाई, परिवहन और वितरण के दौरान पर्याप्त डिजिटल एवं भौतिक सुरक्षा नहीं होने से गोपनीयता भंग हो जाती है। बेरोजगारी और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के चलते तथा सीमित नौकरियों और सीटों के कारण परीक्षा पास करने का दबाव बहुत अधिक है। कुछ अभ्यर्थी गलत रास्ता अपनाने को लालायित हो जाते हैं। सोशल मीडिया के टेलीग्राम, व्हाट्सऐप, ब्लूटूथ डिवाइस, डार्क वेब और हैकिंग तकनीकों का उपयोग कर प्रश्नपत्र तेजी से विस्तारित होने लगते हैं। अपराधियों को पकड़ लिए जाने के बावजूद लंबी कानूनी प्रक्रिया और दोषसिद्धि दर कम होने के कारण अपराधियों में दंड का डर कम दिखाई देता है।

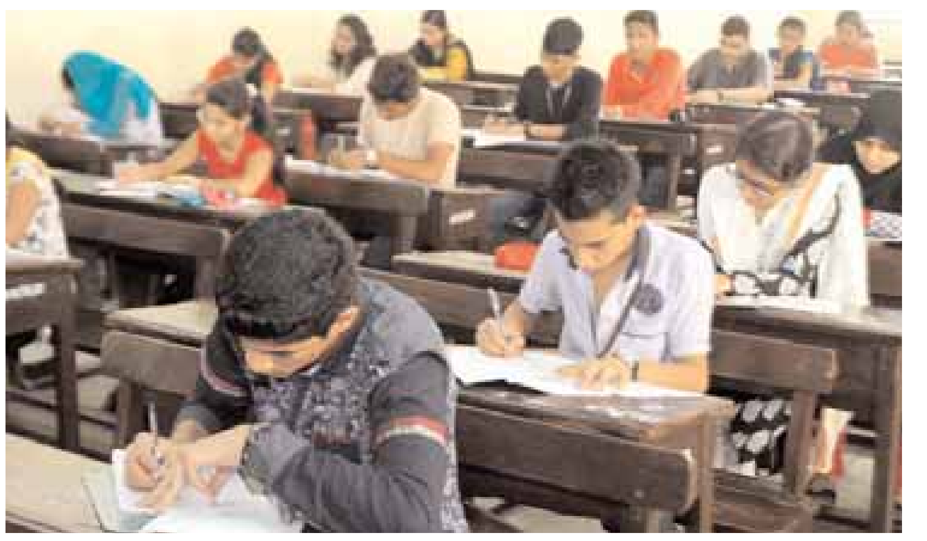

घटनाओं के हो जाने के बाद एक बना बनाया रवैया अपना लिया जाता है। मामलों की जांच सीबीआई याने केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी जाती है। इस जांच के परिणाम और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही इतनी देर से हो पाती है कि छात्रों की प्रवेश की उम्र ही निकल जाती है।

खबरों के अनुसार हाल ही की 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी (NEET-UG 2026) परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जांच बहुत तेज हो गई है और इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, बताया जाता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में मास्टरमाइंड्स सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें दिल्ली की एक अदालत ने 7 दिनों की CBI हिरासत में भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पेपर बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ही लीक किया गया, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के किसी करीबी या अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका भी हो सकती है।

अब होगा यह कि आरोपियों के खिलाफ वित्तीय जांच शुरू कर दी जाएगी, संदिग्धों के संपत्तियों का पता लगाया जाएगा। सीबीआई द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की जाएगी और आरोपियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज, जाली स्टैम्प और हार्ड डिस्क आदि को अपने कब्जे में लिया जाएगा या यह सब अब तक किया भी जा चुका हो। समाचार है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा फिर से कराने की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि पूर्व में ऐसे मामलों में ऐसी ही कार्यवाहियां होती रही हैं फिर भी बार बार पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं क्यों हो जाती है? इनका स्थाई निदान करने में सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? यद्यपि सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए विशेषज्ञ अनेक सुझाव देते रहे हैं। तकनीकी, प्रशासनिक और कानूनी सुधार के साथ माफिया की पहचान और उन पर प्रभावी लगाम सख्ती से लगाने की बातें भी खूब कही गईं हैं। पूरी तरह डिजिटल परीक्षा, डिजिटल रूप से प्रश्न पत्रों कुछ मिनट पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाना जो केवल पास वर्ड की मदद से ही खुल सकें, एआई तथा बायो मीट्रिक तकनीक सत्यापन से डमी कैंडिडेट को रोका जाना साथ ही पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपयों के जुर्माने के सुझाव और नियम कानूनों के उपरांत भी घटनाओं का होना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। संदेह जताया जाता है कि अक्सर पेपर लीक के तार बड़े कोचिंग संस्थानों या संगठित अपराधियों से जुड़े होते हैं। यह सोचा जाना चाहिए कि सरकार द्वारा कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त पंजीकरण और निगरानी प्रणाली विकसित करने में देरी क्यों हो जाती है।

मेडिकल और कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए दुनिया भर मेंप्रवेश की प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं। कई देशों में कठिन प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो केवल स्कूल के अंकों (12वीं या हायर सेकेंडरी) के आधार पर प्रवेश देते हैं।जिन देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती (या अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रक्रिया सरल है)। यहाँ मुख्य रूप से 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अंकों के आधार पर प्रवेश मिल जाता है उनमें रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रोमानिया, जॉर्जिया देश शामिल हैं। क्या हम व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं की बजाए इसी तरह हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं? ऐसा होने से हमारी स्कूली शिक्षा का स्तर भी उल्लेखनीय रूप से गुणवत्तापूर्ण हो सकेगा।

बच्चों का भविष्य बचाने के लिए केवल तकनीक काफी नहीं है, बल्कि एक 'नैतिक संस्कृति' विकसित करने की जरूरत है। जब तक परीक्षा कराने वाली एजेंसियां, प्रिंटिंग प्रेस और केंद्र अधीक्षक पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण सुरक्षा कठिन है। पेपर लीक केवल परीक्षा से जुड़ी तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह युवाओं के विश्वास, सामाजिक न्याय और राष्ट्र की प्रतिभा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। यदि योग्य और मेहनती विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो देश की शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होगी। इसलिए सरकार, परीक्षा एजेंसियों, तकनीकी विशेषज्ञों और समाज को मिलकर ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

सेप्सिस का अदृश्य खतरा और हमारी स्वास्थ्य रणनीति

स्वास्थ्य

कुमार सिद्धार्थ एवं डॉ. सम्यक जैन

हमारे देश के मौजूदा स्वास्थ्य परिदृश्य में, जहां डेंगू, मलेरिया, टीबी, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियां पहले से ही भारी दबाव पड़ रही हैं, सेप्सिस एक ऐसा खतरा बनकर उभर रहा है जो अक्सर नज़र नहीं आता, लेकिन सबसे घातक साबित होता है। देश के अस्पतालों में सेप्सिस अब एक रोज़मर्रा की हकीकत बन चुका है। गहन चिकित्सा कक्ष (ICU) में भर्ती हर चौथा मरीज़ किसी न किसी संक्रमण से उपजी सेप्सिस जैसी गंभीर स्थिति में पाया जाता है। नवजात मृत्यु के कारणों की पड़ताल करें तो लगभग एक-तिहाई मौतें सीधे सेप्सिस से जुड़ी मिलती हैं।

ग्रामीण भारत में यह स्थिति और भी घातक रूप ले लेती है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं और संक्रमण की पहचान अक्सर देर से होती है। कई बार समय पर एंटीबायोटिक या सही हस्तक्षेप न मिलने पर मरीज़ कुछ ही घंटों में मौत के करीब पहुंच जाता है।

दरअसल, सेप्सिस को केवल संक्रमण की जटिलता मानना भ्रामक है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अनियंत्रित होकर अपने ही अंगों पर हमला करने लगती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है और संक्रमण से पैदा हुई सूजन पूरे शरीर में फैलकर दिल, फेफड़ों, गुर्दों और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा देती है। सरल शब्दों में, सेप्सिस संक्रमण के कारण शरीर का अपने ही खिलाफ सिर उठाना है। और, यही इसे इतना घातक और उग्र बना देता है।

हमारे देश में सेप्सिस की भयावहता इस बात से भी साफ होती है कि अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज़ों के लिए मृत्यु का बड़ा कारण अब यही बनता जा रहा है। नवजात शिशुओं में यह स्थिति कई बार जन्म के तुरंत बाद होने वाले संक्रमणों से उभरती है। प्रसूता-गर्भवती महिलाओं, बुज़ुर्गों और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

हमारे देश में सेप्सिस एक छिपी महामारी की तरह व्यवहार करता है। अन्य बीमारियों की अंतिम और सबसे घातक कड़ी अक्सर यही बनता है। इसलिए सेप्सिस को अब एक अलग स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में देखने और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए विशेष रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है।

आंकड़े बताते है कि दुनिया भर में सेप्सिस हर साल एक करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान लेता है, जो वैश्विक मौतों का पांचवां हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ के अध्ययन बताते हैं कि सेप्सिस की सर्वाधिक मार निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ती है, जिनमें भारत भी शामिल है। अपने देश में वर्ष 2017 के अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ 13 लाख मामले और करीब 29 लाख मौतें इसी के कारण हुई हैं। आईसीयू आधारित शोध बताते हैं कि देश के गहन चिकित्सा कक्षों में हर दो में से एक मरीज़ किसी न किसी रूप में सेप्सिस से पीड़ित पाया जाता है, और ऐसे मरीज़ों की अस्पताल मृत्यु दर 30-40 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। नवजात शिशुओं में यह बोझ और भी भारी है, जहां करीब एक-तिहाई मौतें संक्रमणजन्य सेप्सिस से जुड़ी पाई गई हैं।

लेकिन इस गंभीर बीमारी पर हो रहे शोध की स्थिति निराशाजनक है। दुनिया और भारत में, सेप्सिस पर होने वाला अधिकांश वैज्ञानिक कार्य अभी भी उस पुराने ढांचे पर टिका है, जिसमें चूहों, खरगोशों, गिनी पिगों, बकरियों, कुत्तों और कभी-कभी बंदरों तक पर प्रयोग किए जाते हैं। इन जानवरों को प्रयोगशाला की परिस्थितियों में जबरन संक्रमित किया जाता है, आंतों में छेद करके बैक्टीरिया फैलाया जाता है या उन्हें बैक्टीरियल

ज़हर की उच्च खुराक दी जाती है। लेकिन मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इन जानवरों से इतनी अलग है कि ऐसे प्रयोगों से मिलने वाले परिणाम मनुष्यों पर लगभग कभी लागू नहीं होते।

पिछले चार दशकों में डेढ़ सौ से अधिक ऐसी दवाएं रही हैं, जो चूहों या अन्य जंतुओं में सेप्सिस का इलाज करती दिखीं, पर मानव परीक्षण में पूरी तरह असफल रहीं। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों, जैसे - स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एनआईएच आदि का निष्कर्ष है कि जंतु-आधारित मॉडल सेप्सिस का मानव स्वरूप समझने के लिए विश्वसनीय साधन नहीं हैं।

अपने देश में भी स्थिति अलग नहीं है। आईसीएमआर के कई प्रतिष्ठित केंद्र, कुछ ऐम्स संस्थान और निजी बायोमेडिकल प्रयोगशालाएं आज भी जंतु-आधारित मॉडल को सेप्सिस अध्ययन का आधार बनाए हुए हैं। इन परीक्षणों की पारदर्शिता कम है और उनसे मिलने वाले वैज्ञानिक परिणाम अत्यंत सीमित। जिस बीमारी के कारण अस्पतालों में लाखों मरीज़ चुपचाप मौत के करीब पहुंच रहे हों, उसके शोध का तरीका अगर मानव-प्रासंगिक न हो तो समाधान हमेशा दूर ही बना रहेगा।

अलबत्ता, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। भारत में कुछ वैज्ञानिक संस्थान नई दिशाएं भी टटोल रहे हैं। आईआईटी मद्रास का ऑर्गन्स-ऑन-चिप्स कार्यक्रम, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) का सेप्सिस प्रेडिक्शन मॉडल, ऐम्?स दिल्ली में नवजात सेप्सिस के लिए विकसित बायोमार्कर और कुछ निजी प्रयोगशालाओं में एआई आधारित सेप्सिस अलर्ट सिस्टम ये सब संकेत देते हैं कि भारत आधुनिक, मानव-आधारित विज्ञान अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दुनिया भर में अब एआई-आधारित निदान और कम्प्यूटेशनल सिमुलेशन को भविष्य की दिशा माना जा रहा है। ये पद्धतियां न केवल अधिक विश्वसनीय हैं, बल्कि जानवरों पर होने वाली क्रूरता और वैज्ञानिक विफलताओं से भी मुक्त हैं।

भारत में सेप्सिस की भयावहता जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से हमें विज्ञान की दिशा बदलने की ज़रूरत है। आधुनिक तकनीकें हमारे सामने उपलब्ध हैं। ज़रूरत सिर्फ यह है कि हम पुरानी, अप्रासंगिक और अमानवीय शोध पद्धतियों को पीछे छोड़कर वैज्ञानिक रूप से अधिक सटीक, मानवीय और प्रभावी मॉडल अपनाएं। सेप्सिस के खिलाफ यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम विज्ञान और संवेदना दोनों के सही मिश्रण के साथ आगे बढ़े। भारत को स्वास्थ्य विज्ञान के इस नए युग में कदम रखने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन न सिर्फ लाखों लोगों की जान बचा सकता है बल्कि अनगिनत जानवरों को अनावश्यक और पीड़ादायक प्रयोगों से भी मुक्त कर सकता है।

कोरट-कचहरियों की सम्मानजनक विदाई का स्वर्णिम दिन

कटाक्ष

शांतिलाल जैन

लेखक स्तंभकार हैं।

सूरज आज पूरब से तो नहीं ही निकला होगा। लोकतंत्र की स्थापना के आठ दशक से भी कम में मुल्क का भ्रष्टाचारियों, अपराधियों से मुक्त हो जाना कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। ऐसी कामयाबी उसी दिन मिला करती है जिस दिन सूरज पूरब से ना निकला हो। मुझे पक्का यकीन है आज सूरज पूरब से तो नहीं ही निकला होगा।

आज हुआ ये श्रीमान् कि इसके पहले कि आला कचहरी में वकील सा। अपने मुवक्किल के निर्दोष होने की अपील-दलील पेश कर पाते, जिरह होती, गवाहों सबूतों की बिला पर अपने मुवक्किल को दोषमुक्त करा पाते ङ्क प्रॉसिक्यूशन ने केस ही वापस ले लिया!!! अभियुक्त पिछली रात नौ बजे तक अपोजिशन में था, अगली सुबह नौ बजे हाकिम के दल में शामिल हो गया। सुबह का भूला था श्रीमान, अगले दिन सुबह घर आ गया था, सो आप उसे भूला नहीं कह सकते। कभी मिला करती थी क्लीन चिटें अदालतों से, अब हाकिम ने मुकदमा वापिस लेकर उसकी जरूरत ही ख़तम कर दी है। रख लें अदालतें अपनी चिटें अपने पास।

हाकिम ने पार्टी का बड़ा और भव्य दफ्तर बनवाया है मगर बाहर डोर-बेल नहीं लगवाई। दरवज्जे पे न्याय का घंटा जो लटकवा लिया है। बजाईए। अंदर जाईए। क्लीन चिट पाईए और पाईए एक मलाईदार ओहदा भी। स्मार्ट लीडर्स करप्शन करके कारागार का रुख नहीं करते, उनके गेट पर लटका न्याय का घंटा बजा लेते हैं और सेफ झोन में प्रवेश कर जाते हैं। 'सत्तापक्ष में कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता और विपक्ष में कोई ईमानदार नहीं होता।' न्यायशास्त्र का ये नया सिद्धांत है, जो इस अवधारणा को स्थापित करता है कि एक विपक्षमुक्त मुल्क ही भ्रष्टाचार मुक्त मुल्क का पर्याय होता है। देखते देखते न विपक्ष में न कोई नेता बचा है न मुल्क में भ्रष्टाचार का कोई आरोपी। इस तरह आज का मुकदमा दीवानी अदालतों में आख़िरी मुकदमा साबित हुआ।

क्रिमिनल केसेस पहले ही अदालतों में पेश होना बंद हो चुके थे। इसे आप कल्लू मिर्ची के केस से समझिए। उसकी बदमाशी का मुआमला सामने आया और हाकिम के नुमाईंदे जेसीबी पर सवार होकर निकल पड़े। देखते देखते उसका मकान ध्वस्त कर दिया गया। लो साहब, हो गया न्याय। धरा रह गया सत्र न्यायालय और बैठे रह गये 'युवर ऑनर'। पड़ीं रह गईं एफआईआर, तफ़्तीश, साक्ष्य, विवेचना, केसडायरी, रिमांड, जमानत, चार्जशीट, भारतीय न्याय संहिता, वकील, मुवक्किल। कोर्ट-कचहरी के चक्कर में अब ना हाकिम पड़ता है न उसके नुमाईंदे। उनकी मर्ज़ी ही 'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' है। मुल्क के आईन में अब अदालतों की जरूरत ही नहीं बची। पूरी न्यायपालिका एक झटके में बेरोज़गार हो गई है। वकीलों, न्यायाधीशों, कचहरी के कारकूनों का रोज़गार छिन गया हैं। जस्टिस सर की बेंच पर नया कोई केस लिस्ट हो नहीं रहा। कारकून खाली बैठे हैं। वकील मुवक्किलों की तलाश में भटक रहे हैं। 'हाजिर हो' की आवाजें गुम हैं, निस्तब्ध निरापद सन्नाटा पसरा पड़ा है। आज का दिन न्यायपालिका की सम्मानजनक विदाई का दिन है।

लोकतंत्र की स्थापना के आठ दशक से भी कम में ही न्यायपालिका की जरूरत का ख़त्म हो जाना कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। ऐसी कामयाबी उसी दिन मिला करती है जिस दिन सूरज पूरब से ना निकला हो। मुझे पक्का यकीन है आज सूरज पूरब से तो नहीं ही निकला होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नीट, लीक और मंशा पर सवाल

व्यंग्य

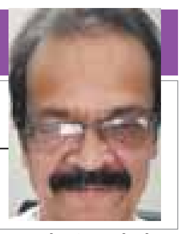

निर्मल गुप्त

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सज्जन जी यह सुन इस तरह मन ही मन हँसे जैसे कोई तपस्वी ज्ञान की जरा-सा आहट पा विहँसे। रूहानियत में आकंठ डूबा आदमी नीट के जरिये ही जीते जी निर्वाण को प्राप्त होता बताया जाता है। फिर उन्हें भान हुआ नीट तक तो ठीक लेकिन यह लीक क्या बला है? मोबाइल पर आने वाली खबरें थोड़ा कसैली तो होती हैं,कभी-कभी अफवाह भी पाई जाती हैं लेकिन ऐसी नहीं होती जिन्हें 'चनडूखाने' वाली बतकही' समझ लिया जाए।

यह उस समय की बात है जब बातों ही बातों में पेपर लीक हो जाया करते थे। एक पेपर लीक होने की अपुष्ट खबर जब एक सज्जन जी के मोबाइल तक जा पहुंची तो वह चिहुंक के बोल उठे - लो जी नीट फिर लीक हो गया। उस वक्त वह मद्धम रौशनी वाले एक पब में बैठे हौले -हौले बजते रूहानी संगीत की संगति में अपने एक सरोकारी मित्र के साथ बैठे रसरंजन कर रहे थे। सज्जन जी ने जो कहा उसके सरोकारी जी महज दो लफ्ज़ सुने। नीट और लीक। वह बोल उठे - नीट तो बर्फ की डली के अधबीच सदा नीट ही रहती है, वह न छलकती है, न लीक होती है, बस सुरूर में झलकती भर है।

सज्जन जी यह सुन इस तरह मन ही मन हँसे जैसे कोई तपस्वी ज्ञान की जरा-सा आहट पा विहँसे। रूहानियत में आकंठ डूबा आदमी नीट के जरिये ही जीते जी निर्वाण को प्राप्त होता बताया जाता है। फिर उन्हें भान हुआ नीट तक तो ठीक लेकिन यह लीक क्या बला है? मोबाइल पर आने वाली खबरें थोडा कसैली तो होती हैं,कभी कभी अफवाह भी पाई जाती हैं लेकिन ऐसी नहीं होती जिन्हें 'चनडूखाने' वाली बतकही' समझ लिया जाए।

सज्जन जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने सरोकारी जी से पूछ ही लिया की ये लीक वीक है क्या बला ? सरोकारी जी ने इस जिज्ञासा को निरर्थक समझ बड़ी अदा के साथ कंधे उचकाए। लगभग कंधे इस तरह से उपर नीचे किये जैसे अमूमन अंग्रेजीदां लोग किसी भी किस्म की बहस से खुद को बचा ले जाने के लिए करते हैं। वैसे भी कंधे उचकाना टाइप का जेस्चर बॉडी लैंग्वेज के व्याकरण के हिसाब से बहुआयामी होती है। अकसर कंधे उचकाता आदमी कमोबेश बड़ा पढ़ा -लिखा सा जेंटलमैन लगता है।

सज्जन जी ने नीट द्रव का बड़ा- सा घूँट भरा और सोचा कि यदि सब कह रहे हैं तो कुछ न कुछ लीक हुआ ही होगा। फिर उन्होंने खुद से प्रतिप्रश्न किया कि आज कोई हमारा वाला टाइम थोड़े हैं कि कमीज में ऊपर लगी जेब में टांगा फोंटेन पैन खुद भी खुद लीक हो कर अच्छी भली शर्ट को डिजाइनर श्रेणी की पोषाक बना दे। वे दिन बड़े भले भले से थे जब परीक्षा शुरू होने से पूर्व लीक हुई स्याही को शुभ शगुन मान लिया जाता था । उन दिनों घर से काम पर जाते हुए कामकाजी गोलाकार टिफिन लेकर उसे झुलाते हुए चलते थे और अफसर टाइप के लोग आयताकार चपटे डिब्बे अपना लंच ब्रीफकेस में रख कर। उन दिनों शायद ही कोई बचा हो जिसके सरकारी कागज या पतलून टिफिन या लंचबॉक्स में रखे अचार के तेल के रिसाव से दागदार न हुए हो।

लेकिन ये नीट का रिसाव या लीक हो जाना तो अद्भुत है। बतातें हैं 'लीकर' इतने निष्णात थे कि बनते ङ्क बनते ही पेपर ले उड़े। इस साइबर काल में गोपनीयता एक निरर्थक शब्द है। इस एआई के जमाने में तो मन की किसी गहरी सतह पर टिकी मंशा तक आननफानन में यदि कभी वायरल हो जाये तो कोई आश्चर्य नहीं। तमाम एआई टूल आपको आपसे अधिक जानते हैं। वे निर्मल और निर्मल में कोई भेद अकसर नहीं करते एक निर्मल के बायो में विविध निर्मलों और समान नामधारी बाबाओं का समावेश कर देते हैं।

सज्जन जी अब समझ गये हैं की कोई नीट कितना भी नीट क्लीन होने का दावा करे पर सेफ नहीं है। इसके बरअक्स सरोकारी जी का कहना है कि सत्ता के ऊपरी सिरे पर कोई भारी गड़बड़ है, जो रह रह कर यहाँ वहां लीकेज होती ही रहती है। वह बिना कंधे उचकाये एलानिया कह रहे हैं कि यदि इसकी सघन जांच हो तो हो न हो इस लीकेज की जड़ें जलडमरू मध्य (जिसे लोग आजकल होर्मुज कहते हैं) में मिलेगी।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस

जयदेव राठी

लेखक अधिवक्ता हैं।

जागरूकता से आगे बढ़कर स्थायी समाधान की जरूरत

विश्व स्तर पर देखा जाए तो डेंगू तेजी से फैलती बीमारियों में शामिल हो चुका है। पहले जिन क्षेत्रों में यह बीमारी नहीं थी, अब वहाँ भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तापमान बढ़ने और मौसम के बदलते पैटर्न ने मच्छरों के जीवन चक्र को प्रभावित किया है। लंबे समय तक गर्मी और नमी बने रहने से मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी बड़ा खतरा बन चुका है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। देश के लगभग सभी राज्यों में डेंगू के मामले सामने आते हैं। महानगरों से लेकर छोटे शहर और गाँव तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हर वर्ष स्थिति गंभीर हो जाती है। सरकारी आँकड़े कई बार वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते क्योंकि बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं या जाँच तक नहीं करवा पाते।

हर वर्ष भारत में 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि उस बढ़ते स्वास्थ्य संकट की याद दिलाने वाला दिन है जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। कभी केवल बरसात के मौसम तक सीमित रहने वाला डेंगू अब पूरे वर्ष चुनौती बनता जा रहा है। बदलती जलवायु, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमजोरियाँ इस बीमारी को और खतरनाक बना रही हैं। डेंगू आज केवल एक बीमारी नहीं बल्कि विकास, पर्यावरण और प्रशासन से जुड़ा बड़ा प्रश्न बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले दो दशकों में डेंगू के मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है और अब यह 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका इसके सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। हर वर्ष लाखों लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं और हजारों परिवार आर्थिक व मानसिक संकट झेलते हैं।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और नई स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि डेंगू को केवल मौसमी बीमारी मानने की गलती न की जाए बल्कि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़कर देखा जाए।

डेंगू मच्छर जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण फैलती है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन के समय काटता है। यही कारण है कि शहरों में घरों की छतों पर रखी टंकियाँ, कूलर, गमले, पुराने टायर और खुले बर्तन इसके सबसे बड़े प्रजनन केंद्र बन जाते हैं। विडंबना यह है कि आधुनिक जीवनशैली और सुविधाएँ ही कई बार बीमारी का कारण बन रही हैं।

विश्व स्तर पर देखा जाए तो डेंगू तेजी से फैलती बीमारियों में शामिल हो चुका है। पहले जिन क्षेत्रों में यह बीमारी नहीं थी, अब वहाँ भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तापमान बढ़ने और मौसम के बदलते पैटर्न ने मच्छरों के जीवन चक्र को प्रभावित किया है। लंबे समय तक गर्मी और नमी बने रहने से मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी बड़ा खतरा बन चुका है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। देश के लगभग सभी राज्यों में डेंगू के मामले सामने आते हैं। महानगरों से लेकर छोटे शहर और गाँव तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हर वर्ष स्थिति गंभीर हो जाती है। सरकारी आँकड़े कई बार वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते क्योंकि बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं या जाँच तक नहीं करवा पाते।

भारत की सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या घनत्व और अव्यवस्थित शहरीकरण है। तेजी से फैलते शहरों में जल निकासी की खराब व्यवस्था, गंदगी और निर्माण स्थलों पर जमा पानी डेंगू के लिए आदर्श परिस्थितियाँ तैयार करते हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और सीमित स्वास्थ्य सुविधाएँ समस्या को और बढ़ा देती हैं।

हालाँकि भारत ने डेंगू नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास भी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। स्कूलों, पंचायतों और शहरी निकायों को इसके नियंत्रण में जोड़ा जा रहा है। कई राज्यों ने विशेष फॉगिंग अभियान, साफ-सफाई अभियान और अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए हैं। भारत में वैज्ञानिक स्तर पर भी डेंगू को लेकर शोध बढ़ा है और वैक्सीन व नई उपचार तकनीकों पर कार्य हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ने यह सीखा कि केवल अस्पताल बढ़ा देने से स्वास्थ्य संकटों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। रोकथाम सबसे प्रभावी उपाय है। डेंगू के मामले में भी यही सत्य है। यदि लोग अपने घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने दें तो बड़ी संख्या में मामलों को रोका जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जागरूकता अक्सर केवल पोस्टर और नारों तक सीमित रह जाती है।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा समाज स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रहा है? कई लोग आज भी यह मानते हैं कि सफाई केवल सरकार का काम है जबकि वास्तविकता यह है कि डेंगू नियंत्रण में नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी लापरवाही पूरे मोहल्ले के लिए खतरा बन सकती है।

इसके साथ ही सरकारों को भी आत्ममंथन करना होगा। हर वर्ष बरसात से पहले डेंगू नियंत्रण की योजनाएँ बनती हैं लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में काम बहुत धीमा है। शहरों की जल निकासी व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, अवैध निर्माण और सार्वजनिक सफाई की समस्याएँ वर्षो से जस की तस बनी हुई हैं। स्वास्थ्य बजट बढ़ाने और स्थानीय निकायों को मजबूत करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

दुनिया के कई देशों ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से डेंगू नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है। सिंगापुर इसका बड़ा उदाहरण है जहाँ कठोर नियमों और जनजागरूकता के कारण डेंगू पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। भारत जैसे विशाल देश में यह चुनौती कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। आवश्यकता केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक योजना और सामाजिक भागीदारी की है। डेंगू का आर्थिक प्रभाव भी कम नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इलाज का खर्च भारी बोझ बन जाता है। निजी अस्पतालों में प्लेटलेट्स और उपचार के नाम पर भारी बिल वसूले जाते हैं। कई बार डर और अफवाहें भी लोगों की परेशानी बढ़ा देती हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और सस्ती चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जरूरी है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस केवल बीमारी की चर्चा करने का अवसर नहीं होना चाहिए बल्कि यह आत्मविश्लेषण का दिन बनना चाहिए। क्या हमारे शहर रहने योग्य बन रहे हैं? क्या विकास योजनाओं में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जब तक इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार नहीं होगा तब तक हर वर्ष डेंगू नए रूप में सामने आता रहेगा। भारत के पास दुनिया को दिशा देने का अवसर भी है। जिस तरह भारत ने वैक्सीन निर्माण, दवाइयों और जनस्वास्थ्य अभियानों में वैश्विक पहचान बनाई है उसी प्रकार डेंगू नियंत्रण में भी वह नेतृत्व कर सकता है। इसके लिए शोध, तकनीक, स्वच्छता और जनभागीदारी को एक साथ जोड़ना होगा।

आज आवश्यकता केवल एक दिवस मनाने की नहीं बल्कि एक स्थायी जनआंदोलन खड़ा करने की है। यदि हर नागरिक सप्ताह में केवल दस मिनट अपने घर और आसपास जमा पानी की जाँच कर ले तो डेंगू के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस का वास्तविक उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि बीमारी के बाद इलाज नहीं, बल्कि बीमारी से पहले बचाव की संस्कृति विकसित हो। डेंगू के खिलाफ लड़ाई सरकार, समाज और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। जब तक यह जिम्मेदारी सामूहिक रूप से नहीं निभाई जाएगी तब तक हर बरसात के साथ अस्पतालों की भीड़, बढ़ती चिंताएँ और स्वास्थ्य संकट की खबरें दोहराई जाती रहेंगी। अब समय आ गया है कि जागरूकता को आदत और अभियान को संस्कृति बनाया जाए।

राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वीडी सतीशन: जमीनी योद्धा का सम्मान

गुरुवार की सुबह सुश्री दीपा दासमुंशी के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन तथा वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की मौजूदगी में इस आशय की घोषणा से अंततः अटकलों का कुहासा छंट गया और यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी नेतृत्व अपने जमीनी योद्धा का चयन करने के मूड में है और केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला कुर्सी की दौड़ में पिछड़ गये हैं। यह ऐलान इसलिये भी मानीखेज था, क्योंकि यह खबर छनकर आ रही थी कि निर्वाचित विधायकों का बहुमत वेणुगोपाल के साथ है, जिन्हें पार्टी में दिल्ली की किल्ली के नजदीक माना जाता है। लेकिन बुधवार की शाम पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माकन, दासमुंशी और वासनिक से विमर्श ने सतीशन का नाम आगे कर दिया। इसके बाद घड़ी के कांटे तेजी से घूमे। गुरुवार की सुबह राहुल गाँधी ने केसी वेणुगोपाल से चर्चा की। तकरीबन तीस मिनट की बातचीत में राहुल अपने निकट सहयोगी को दौड़ से हटने के लिये मनाने में सफल रहे और इसके कुछ घंटों बाद विधिवत वीडी के नाम की घोषणा कर कर दी गयी।

वदासरी दामोदरन (वीडी) सतीशन अब साक्षर-राज्य केरलम के मुख्यमंत्री होंगे। दस दिनों की माथा-पच्ची और रायशुमारी के उपरांत अंततः 14 मई को दिल्ली में उनके नाम का ऐलान हो गया। गुरुवार की सुबह सुश्री दीपा दासमुंशी के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन तथा वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की मौजूदगी में इस आशय की घोषणा से अंततः अटकलों का कुहासा छंट गया और यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी नेतृत्व अपने जमीनी योद्धा का चयन करने के मूड में है और केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला कुर्सी की दौड़ में पिछड़ गये हैं। यह ऐलान इसलिये भी मानीखेज था, क्योंकि यह खबर छनकर आ रही थी कि निर्वाचित विधायकों का बहुमत वेणुगोपाल के साथ है, जिन्हें पार्टी में दिल्ली की किल्ली के नजदीक माना जाता है। लेकिन बुधवार की शाम पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माकन, दासमुंशी और वासनिक से विमर्श ने सतीशन का नाम आगे कर दिया। इसके बाद घड़ी के कांटे तेजी से घूमे। गुरुवार की सुबह राहुल गाँधी ने केसी वेणुगोपाल से चर्चा की। तकरीबन तीस मिनट की बातचीत में राहुल अपने निकट सहयोगी को दौड़ से हटने के लिये मनाने में सफल रहे और इसके कुछ घंटो बाद विधिवत वीडी के नाम की घोषणा कर कर दी गयी।

31 मई, सन् 1964 को नेत्तूर में जनमे सतीशन खाँटी कांग्रेसी नेता हैं। छात्र जीवन में वह एनएसयूआई से जुड़ गये। सन् 1986-87 में वह महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे। यूनिवर्सिटी आफ केरल से उन्होंने एलएलएम किया और हाईकोर्ट में दस साल प्रैक्टिस। सन् 1996 में उन्होंने परवूर से असेंबली का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन 'प्रथम ग्रासे मक्षिकापातः' की तर्ज पर वह सीपीआई के पी. राजू से हार गये। सन 2001 के चुनाव में उन्होंने राजू हिसाब चुकता किया और इसके बाद क्रमशः केएम दिनकरन, रवीन्द्रन, शारदा मोहन और एमटी निक्सन जैसे नेताओं को हरा कर लगातार असेंबली में पहुंचे। सन 2021 में रमेश चेन्निथला के स्थान पर नेता प्रतिपक्ष बने और तदंतर विधानसभा के भीतर और बाहर अपनी सक्रियता से सबका ध्यान आकृष्ट किया। केरलम के कांग्रेस नेताओं में वह संघर्ष, साख और सक्रियता के मामले में सबसे आगे हैं। कोट्टायम के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक निजाम सैयद के मुताबिक सतीशन इज द बेस्ट च्वॉयस फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। जनभावनाओं का ज्वार उनके साथ है और कार्यकर्ता उनके पीछे।

आखिर क्या वजह है कि निजाम व अन्य मलयाली पत्रकार सतीशन को 'सर्वोत्तम पसंद' निरूपित कर रहे हैं वजह साफ है। सतीशन जमीनी योद्धा है और आडंबर से कोसों दूर। वह कुशल और प्रभावशाली वक्ता हैं और उन्हें सुनना 'सांद्र अनुभव' से गुजरना है। वह लेखक तो नहीं, अलबत्ता गंभीर पाठक हैं और साहित्यिक जलसों में उन्हें आग्रहपूर्वक बुलाया जाता है। आधुनिक मलयाली साहित्य में उनकी गहरी रूचि है और वह जेन-जी में बेहद लोकप्रिय है। उन्हें सियासी नजूमी भी माना जा सकता है, क्योंकि चुनावों में उनकी भविष्यवाणियाँ खरी उतरती रही हैं। इस दफा तो उन्होंने सार्वजनिक ऐलान कर कर दिया था कि यदि यूडीएफ को सौ से कम सीटें मिलीं तो वह राजनीति सन्यास ले लेंगे। केरलम में काँग्रेसनीत गठबंधन को जिताने में उन्होंने रात-दिन एक कर दिया। पार्टी में उन्हें 'टास्क मास्टर' माना जाता है और इसके चलते वह प्रियंका और राहुल के विश्वासपात्र बनकर उभरे। मासांत में वह अपना 62वीं वर्षगांठ बतौर सीएम मनायेंगे। उनका टास्क मास्टर होना यकीनन उम्मीदें जगाता है। त्रिवेंद्रम और दिल्ली में चले दस दिनी घटनाक्रम ने यह भी दर्शा दिया कि महत्वाकांक्षी शशि थरूर के नाम पर कहीं कोई विचार नहीं किया गया।

यात्रा संस्मरण

मोहन वर्मा

लेखक पत्रकार हैं।

रोमांच, आस्था और प्रकृति का अद्भुत सफर

देवास की 44 डिग्री तापमान वाली तपती गर्मी से निकलकर हम तीन मित्र पहुँचे हल्द्वानी। हल्द्वानी से कुछ दूरी पर स्थित काठगोदाम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहीं से पहाड़ों का वास्तविक सफर शुरू होता है। घुमावदार सड़कें, बादलों से घिरी पहाड़ियाँ और घाटियों में बहती नदियाँ मन को रोमांच से भर देती हैं। सड़क मार्ग से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे पिथौरागढ,जो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। वहाँ से हमारा कारवाँ पहुँचा धारचूला, जो भारत-नेपाल सीमा पर बसा एक सुंदर कस्बा है। इसके साथ-साथ बहती काली नदी का हरा, निर्मल जल और कल-कल करता प्रवाह मन को मोह लेता है। नदी के एक ओर भारत और दूसरी ओर नेपाल की बस्तियाँ दिखाई देती हैं। यही रास्ता आगे कैलाश मानसरोवर, आदिकैलाश और ओम पर्वत तक जाता है।

पर्यटन प्रेमी और घुमक्कड़, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, हर जगह मिल जाते हैं। कोई प्रकृति की अनुपम सुंदरता देखने निकलता है तो कोई दुर्गम पहाड़ों में बसे आस्था के केंद्रों की ओर खिंचा चला जाता है। हिमाचल, सिक्किम, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारधाम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और अंडमान-निकोबार की यात्राओं के बाद इस बार हमारा कारवां निकला आदिकैलाश और ओम पर्वत की ओर।

देवास की 44 डिग्री तापमान वाली तपती गर्मी से निकलकर हम तीन मित्र पहुँचे हल्द्वानी। हल्द्वानी से कुछ दूरी पर स्थित काठगोदाम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहीं से पहाड़ों का वास्तविक सफर शुरू होता है। घुमावदार सड़कें, बादलों से घिरी पहाड़ियाँ और घाटियों में बहती नदियाँ मन को रोमांच से भर देती हैं।

सड़क मार्ग से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे पिथौरागढ,जो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। वहाँ से हमारा कारवाँ पहुँचा धारचूला, जो भारत-नेपाल सीमा पर बसा एक सुंदर कस्बा है। इसके साथ-साथ बहती काली नदी का हरा, निर्मल जल और कल-कल करता प्रवाह मन को मोह लेता है। नदी के एक ओर भारत और दूसरी ओर नेपाल की बस्तियाँ दिखाई देती हैं। यही रास्ता आगे कैलाश मानसरोवर, आदिकैलाश और ओम पर्वत तक जाता है।

रास्ते में सबसे पहले हमने दर्शन किए नीम करौली बाबा के आश्रम के। देशभर से श्रद्धालु यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। पहाड़ों की शांत वादियों में स्थित यह धाम मन को अद्भुत सुकून देता है। इसके बाद हम पहुँचे चितई गोलू देवता मंदिर, जहाँ विराजते हैं पहाड़ों के न्याय के देवता गोलू देव। यहाँ लोग अपनी पीड़ा और अन्याय की अर्जियाँ मंदिर में बाँधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर घंटियाँ चढ़ाकर आभार व्यक्त करते हैं। मंदिर में टंगी हजारों घंटियाँ और अर्जियाँ इस अटूट विश्वास की गवाही देती हैं कि देवता सबकी सुनते हैं। हमारे सफर का अगला पड़ाव था जागेश्वर धाम। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित यह प्राचीन मंदिर परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। कहा जाता है कि आदिकैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा का आध्यात्मिक आरंभ यहीं से होता है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस परिसर में सवा सौ से अधिक शिवलिंग स्थापित हैं, जहाँ पहुँचकर मन स्वतः ही शांत हो जाता है।

शाम ढलते-ढलते हमारा कारवां पहुँचा गुंजी गांव। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम अपने होम-स्टे पहुँचे। अगली सुबह जब हम लगभग पंद्रह हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित आदिकैलाश पहुँचे, तो सामने फैली हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं ने मानो मन को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान शिव हिमालय की गोद में विराजमान हों। ढाई किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान पार्वती कुंड, भीम खेत और गौरीकुंड के दर्शन हुए। बर्फीली हवाओं और शांत वातावरण के बीच यह अनुभव शब्दों से परे था।

अगली सुबह हम निकले ओम पर्वत की ओर। दुर्गम रास्तों और ऊँचे पहाड़ों के बीच जब दूर बर्फ से ढकी चोटी पर प्राकृतिक रूप से बनी 'ऊँ' की आकृति दिखाई दी, तो मन श्रद्धा से भर उठा। उस क्षण केवल 'ऊँ नमः शिवाय' का जाप ही हृदय में गूंज रहा था।

ओम पर्वत के दर्शन के बाद हमारी वापसी यात्रा शुरू हुई। हम फिर पहाड़ों की ठंडक छोड़कर मालवा की धरती और 43-44 डिग्री तापमान में लौट आए। सहयात्री भाई श्रीकांत पटवा और राहुल परमार के साथ आदिकैलाश और ओम पर्वत की यह रोमांचक, आध्यात्मिक और अविस्मरणीय यात्रा हमेशा के लिए हमारे मन और स्मृतियों में बस गई।

3 माह से वेतन नहीं मिलने पर आशा, उषा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे

पैसा नहीं तो काम नहीं

धार। धार जिले के सभी विकासखण्ड के आशा, उषा कार्यकर्ता आशा पर्यवेक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर पूरे धार जिले के सभी ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता ने शुक्रवार से काम बंद कर दिया और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। घर परिवार की स्थिति ख़राब है, घर-परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। इस सम्बन्ध में वेतन लम्बे समय से नहीं मिलने को लेकर 8 मई को आशा,उषा सहयोगी संगठन की जिलाध्यक्ष संगीता मारु मोयाखेड़ा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर कलेक्टर और सीमीएचओ मुख्यालय पर ज्ञापन भी दिया गया था, चर्चा कर बताया भी गया था कि 14 मई तक वेतन नहीं निकलता है तो जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर 15 मई से जिले के समस्त आशा

कार्यकर्ता,उषा आशा पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे।

आशा उषा आशा पर्यवेक्षक संगठन के इंदौर संभागीय अध्यक्ष शंकरलाल मारु ने बताया कि वेतन की मांग को लेकर धार जिले के सभी ब्लॉक में कहां पर मेडिकल ऑफिसर तो कही पर बी पी एम , बीसीएम को ज्ञापन दिया गया है । शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरने सम्बन्धित ज्ञापन सौंपा गया।

मध्य प्रदेश आशा कार्यकर्ता, उषा, आशा पर्यवेक्षक संगठन के इंदौर संभागीय अध्यक्ष शंकरलाल मारु मोयाखेड़ा ने बताया कि जिले में भी कभी पूछो तो बताते है नहीं है पेमेंट, ना कभी फोन उठाते हैं और काम करवाने के लिए जिले और ब्लॉक के अधिकारी कलेक्टर और एसडीएम की धमकी देते हैं ।

बिजली की बदहाली के खिलाफ आधी रात में चक्काजाम, नगर हित में सब नागरिक एक

सोहागपुर। नगर में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था और घंटों की अघोषित कटौती एवं बदहाली के विरोध में शुक्रवार देर रात नागरिकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गत दिवस शाम 6 बजे से शुरू हुई बिजली कटौती रात 2 बजे तक जारी रही। इससे परेशान होकर भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं सैकड़ों नागरिकों ने बिजली विभाग कार्यालय के समीप पेट्रोल पंप चौराहे पर चक्का जाम कर दिया।

करीब डेढ़ घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नाराज़गी जाहिर की। तहसीलदार राकेश खजूरिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को समझाने का प्रयास किया,।लेकिन नागरिक एसडीएम एवं डीजीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बताया गया कि एसडीएम प्रियंका भल्लावी अपने मुख्यालय पर मौजूद नहीं थीं।जिसके चलते वह मौके पर नहीं पहुंच सकीं। इस बात को लेकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पीड़ितों का कहना था कि जब शहर की जनता रातभर सड़कों पर परेशान खड़ी है, तब जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय से नदारद हैं। स्थिति तब शांत हुई जब बिजली विभाग के डीजीएम मौके पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज ने तीखे शब्दों में नगर की चरमराई बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तत्काल सुधार की मांग की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के रवैये पर भी नाराज़गी जताई और चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा। ब्लाक भाजपा अध्यक्ष अश्विनी सरोज ने कहा कि नगर हित में हम कांग्रेस-भाजपा नहीं करते, हम सिर्फ नगर के लोगों की बात करते हैं। हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। नगर के नागरिकों को यदि कोई अधिकारी अपने तानाशाही रवैये से परेशान करेगा । तो हम सब एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। जनता सड़क पर है और जिस अधिकारी के हाथ में शहर का लॉ एंड ऑर्डर है, वही मुख्यालय से गायब है।

सरकार की जनहितैषी योजनाओं पर ऐसे लापरवाह अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। यदि अधिकारी मुख्यालय पर नहीं रह सकते तो अपना तबादला कराकर गांव चले जाएं।÷ पीड़ितों ने बिजली विभाग को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि नगर की बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। चक्का जाम में भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज, भाजपा युवा जिला उपाध्यक्ष अभिनव पालीवाल, कांग्रेस युवा नेता प्रशांत मालवीय, विजय छावड़िया (नन्नू भैय्या) पार्षद आशीष विश्वकर्मा, श्रीकांत रघुवंशी सहित भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर के सैकड़ों नागरिक मौजूद उपस्थित थे।

श्रीमद्भागवत कथा के अवसर पर निकाली कलशयात्रा, शामिल हुए महामंडलेश्वर स्वामी अनिल आनंद महाराज जी

(हीरालाल गोलानी)

भोपाल। इन्द्रविहार पंचवटी कालोनी के शिव झूलेलाल मंदिर से श्री श्री सत्य अनंत माधवाय नमः विश्व सनातन धर्म - श्री महाकालेश्वर मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा,जगन्नाथ संस्कृति, भविष्य मलिका पुराण, श्री विष्णु महायज्ञ, मानव कल्याण के लिए के 15 से 21 मई को होने वाली कथा के रहे थे। वहीं आयोजक पंकज खूबचदानी ने अपने सिर पर श्रीमद्भागवत पुराण लेकर चल रहे थे। इसके साथ रास्ते पर जल छिड़का जा रहा था। कलशयात्रा कालोनी के विभिन्न मार्गो पर होकर भोपाल के विख्यात भोपाल गर्ल्स स्कूल पंचवटी एयरपोर्ट रोड लालघाटी पर पहुंची। इस गरिमामय शोभायात्रा में महामंडलेश्वर

अवसर पर भव्य कलशयात्रा निकाली गई। इस गरिमामय कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी अनिल आनंद महाराज जी खाटूश्यामजी मंदिर सिन्धी कालोनी भोपाल शामिल हुए। शिव झूलेलाल मंदिर से निकली कलशयात्रा के प्रथम में डीजे द्वितीय में नीरजा गोलानी खूबचदानी के द्वारा निर्मित आकर्षक जगन्नाथपुरी मंदिर की आकृति को सिर लेकर चल रहे थे। बारी बारी से दोनों कालोनियों के नागरिक सिर उठाकर चल रहे थे।

इस कलश यात्रा में मातृशक्ति कलश हुई थी। वहीं गणमान्य नागरिक डांडिया नृत्य करते चल रहे थे। डीजे की धार्मिक धुनों पर मातृशक्ति एवं गणमान्य नागरिक भी झूमते नजर आ स्वामी अनिल आनंद महाराज जी खाटूश्यामजी मंदिर सिन्धी कालोनी, आयोजक खूबचदानी परिवार के सदस्य सहित कई गणमान्य नागरिक एवं मातृशक्ति उपस्थित थे।भोपाल गर्ल्स स्कूल पंचवटी परिसर में उड़ीसा के कथा वाचक व्यास जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान परम पूज्य पंडित डॉ. श्री काशीनाथ मिश्र जीके मुखारविंद से होगा। कथा आज से प्रारंभ होकर 21 मई को कथा को विराम दिया जाएगा। कथा शाम 5 से 8 बजे तक होगी। उल्लेखनीय है कि जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान डॉ. काशीनाथ जी मिश्र टोरंटो कनाडा सहित भारत कई प्रान्तों में अपने मुखारविंद से कथा का आयोजन कर चुके हैं।

स्थानीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रशिक्षण संपन्न

सोहागपुर। जनपद पंचायत के सभा कक्ष में स्थानीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष 2026 के संबंध में बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने निर्धारित प्रपत्रों के सही उपयोग एवं समय सीमा में कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्राधिकृत कर्मचारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया, दिशा-निर्देश एवं आवश्यक सावधानियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची को अद्यतन करने संबंधी आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटिरहित होना लोकतांत्रिक

प्रक्रिया की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः समस्त सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ कार्य करने का आग्रह किया गया। जनपद पंचायत सोहागपुर के सभा कक्ष में, प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर राहुल तिवारी विपिन गिल्ला अमित मिश्रा संदीप कुशवाहा ने सभी संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया।

तमाम प्रयासों के बाद भी सरकारी स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या

लक्ष्य के मुकाबले 92.93 प्रतिशत ही नामांकन

एस. द्विवेदी

बैतूल। जिले में हर साल बच्चों के नामांकन संख्या में कमी आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक कुल 2 लाख 81 हजार 744 विद्यार्थियों के प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक 2 लाख 61 हजार 788 विद्यार्थियों का ही नामांकन हो सका है। यह लक्ष्य के मुकाबले 92.92 प्रतिशत है। आमला में 30173 आठनेर में 16858, बैतूल में 52342, भैंसदेही में 23901, भीमपुर में 25293, चिचोली में 16271, घोड़ाडोंगरी में 35056, मुलताई में 25609, प्रभातपट्टन में 16563 और शाहपुर में 19722 बच्चों का नामांकन हो पाया है। जबकि बीते साल जिलेभर के स्कूलों में प्री-प्रायमरी से 12वीं तक 2 लाख 81 हजार 744 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा 57436 बच्चे बैतूल ब्लॉक में थे। इनके अलावा घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में 37350, आमला में 31113, आठनेर में 18202, भैंसदेही में 26274, भीमपुर में 27984, चिचोली में 17495, मुलताई में 27766, प्रभातपट्टन में 17299

और शाहपुर ब्लॉक में 20825 बच्चे दर्ज थे। इस साल भी विभाग द्वारा इतने बच्चों का नामांकन किए जाने का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि इस साल इतने बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है प्रवेश अभियान अभी जारी है और शेष बच्चों को स्कूलों से जोडने के लिए लगातार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान, पलायन और प्रारंभिक कक्षाओं में अभिभावकों की कम रुचि नामांकन घटने के प्रमुख कारण हो सकते हैं।

प्री-प्राइमरी कक्षाओं की स्थिति कमजोर- सबसे कमजोर स्थिति प्री-प्राइमरी कक्षाओं में सामने आई है। यहां 14 हजार 888 बच्चों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 10 हजार 464 बच्चों का ही प्रवेश हुआ, जो मात्र 70.28 प्रतिशत है। भीमपुर ब्लॉक में तो हालात सबसे खराब रहे, जहां लक्ष्य के मुकाबले केवल 23.81 प्रतिशत बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया। वहीं शाहपुर में 49.06 प्रतिशत, आठनेर में 59.55 प्रतिशत और भैंसदेही में 64.11 प्रतिशत नामांकन ही हो सका। हालांकि कक्षा 1 से 8 तक की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही। यहां 1 लाख 86 हजार 330 के लक्ष्य के मुकाबले 1 लाख 72 हजार 099 विद्यार्थियों का प्रवेश दर्ज किया गया, जो 92.36 प्रतिशत है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक कई ब्लॉकों ने लक्ष्य से अधिक नामांकन दर्ज किया। आमला में 108.33 प्रतिशत, आठनेर में 100.59 प्रतिशत और शाहपुर में 103.49 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है।

शिक्षक और सुविधाओं की कमी भी एक बड़ा कारण

यदि जिले के सरकारी स्कूलों पर नजर डाली जाये तो सरकारी स्कूलों में प्रायमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक 93.87 प्रतिशत ही बच्चों को नामांकन हुआ है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन का लक्ष्य 188637 निर्धारित किया था, जिसके एवज में 177073 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। इसके पीछे जानकारों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में एक तो शिक्षक पर्याप्त नहीं है, कई स्कूल में एक शिक्षक को 5-5 कक्षाएं संभालना पड़ रहा है। इसके अलावा कई स्कूल भवन जर्जर है। उसमें बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर निजी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक होते है और पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होता है। जिसकी वजह से पालक सरकारी स्कूलों की बजाये निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना बेहतर समझते है। ग्रामीण क्षेत्र तक में लोग स्थानीय सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाए शहर के निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते है। कुछ स्कूलों के हालात तो ऐसे है, जहां महज 1 से 10 बच्चे ही है।

नामांकन बढ़ाने किये जाते हैं कई प्रयास

सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़ सके, लेकिन शासन के तमाम प्रयासों के बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात नहीं सुधर पा रहे है। परिणाम सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होते जा रही है। जबकि सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल लाने के लिए स्कूल चले हम अभियान चलाया जा रहा है। घर-घर दस्तक देकर सर्वे किये जाते है। सरकारी स्कूलों में पढने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तके, ड्रेस और आने-जाने के लिए साइकिलें वितरित की जाती है। इसके बाद भी नामांकन के मामले में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। इसे लेकर जिला कलेक्टर भी समीक्षा बैठक में नाराजगी जता चुके है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित कर लक्ष्य अनुसार प्रगति लाये।

जिले के स्कूलों में नामांकन की स्थिति

ब्लाक	लक्ष्य	नामांकन
आमला	31113	30137
आठनेर	18202	16858
बैतूल	57436	52342
भैंसदेही	26274	23901
भीमपुर	27984	25293
चिचोली	17495	16271
घोड़ाडोंगरी	37350	35056
मुलताई	27766	25609
प्रभातपट्टन	17299	16563
शाहपुर	20825	19722
कुल	281744	261788

इनका कहना है –

हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में नामांकन की स्थिति बेहद अच्छी है। अभी तक लक्ष्य का 98.38 प्रतिशत टारगेट हासिल किया जा चुका है। जो शेष बच गया है, उसे भी पूरा कर लिया जायेगा।

– **भूपेन्द्र वरकड़े,** जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल

- लक्ष्य के मुताबिक नामांकन के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे है। इसके लिए समय-समय पर बैठक भी ली जा रही है, जिसमें नामांकन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को कहा जा रहा है। उम्मीद है कि हम लक्ष्य को हासिल कर लेगे।

– **सुधीर साकेत,** डीपीसी, बैतूल

पटाखा दुकानों और मैगजीन का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों के पालन के दिए निर्देश

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार शुक्रवार को एसडीएम बैतूल डॉ. अभिजीत सिंह ने एसडीओपी बैतूल सुनील लाटा के साथ बैतूल क्षेत्र स्थित अनुज्ञाधारी मैगजीन एवं फायर वर्क्स पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान एवं गोदाम में पटाखों के भंडारण, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान दुकान के लाइसेंस एवं

अनुमति पत्रों का परीक्षण किया गया। साथ ही अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं उनकी वैधता की जांच की गई। अधिकारियों ने सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, निर्धारित सुरक्षा मानकों के पालन, विद्युत व्यवस्था तथा आग से बचाव संबंधी उपायों का भी निरीक्षण किया। एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्टॉक एरिया के चारों ओर बाउंड्री वॉल को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। मैगजीन परिसर के आसपास मौजूद सूखी झाडियों एवं घास की नियमित साफ-सफाई कराने को कहा, ताकि आग लगने जैसी घटनाओं की संभावना को रोका जा सके। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति एवं अग्निशमन कार्य के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, परिसर में सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा अग्नि सुरक्षा उपकरणों का नियमित परीक्षण एवं रख-रखाव करने के निर्देश भी संबंधित संचालकों को दिए गए।

फव्वारा चौक पर रास्ते की भूमि पर निर्माण रुका, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लगाई रोक

जनसुनवाई में शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन, तहसीलदार व थाना प्रभारी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

बैतूल। मुलताई नगर के व्यस्ततम क्षेत्र फव्वारा चौक पर मुख्य मार्ग से लगी नगर पालिका सडक़ की भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। जनसुनवाई में शिकायत सामने आने के बाद तहसीलदार डॉ. संजय कुमार बरैया, थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार, राजस्व अमला तथा नगर पालिका टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि विवेकानंद वार्ड स्थित फव्वारा चौक के सामने मुख्य मार्ग से लगी भूमि पर रतन सिंह द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। शिकायतकर्ता हरप्रीत खुराना ने जनसुनवाई में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि निर्माण सार्वजनिक मार्ग के लिए दर्ज भूमि पर किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की।

सीमांकन के लिए गठित हुआ जांच दल

मामले की शिकायत के बाद तहसीलदार न्यायालय द्वारा सीमांकन और जांच के लिए विशेष राजस्व दल गठित किया गया था। जांच दल में राजस्व आरआई नजूल अशोक राठौर, आरआई शिवकुमार चौरासे, पटवारी सोहबत धुर्वे तथा पटवारी आशीष गामड़ शामिल थे। जांच दल ने फव्वारा चौक स्थित नजूल भूमि, सीट नंबर-21 के भूखंड क्रमांक 87/2, क्षेत्रफल 229.95 वर्गमीटर का मौका निरीक्षण किया। अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि की नपाई कर पंचनामा तैयार किया गया।

प्रशासन बोला– न्यायालय में मामला लंबित, तब तक नहीं होगा निर्माण

मौके पर पहुंचे तहसीलदार डॉ. संजय कुमार बरैया ने राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण किया तथा जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित भूमि स्वामी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज मार्ग क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाए। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने भी दोनों पक्षों को आपसी सहमति और कानून के दायरे में रहकर विवाद का समाधान निकालने की समझाइश दी। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा थाना मुलताई में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी।

वैज्ञानिक भंडारण से गरीबों तक राशन पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया से रूबरू हुए युवा

युवाओं ने सरकारी भंडार गृह रायसेन बम्होरी में समझी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जमीनी व्यवस्था

रायसेन (निप्र)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित ''मेरा युवा भारत'' जिला रायसेन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रथम दिवस पर युवाओं ने सरकारी भंडार गृह रायसेन का शैक्षणिक भ्रमण कर खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को नजदीक से समझा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओंए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तथा वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली से व्यावहारिक रूप से परिचित कराना रहा।

कार्यक्रम के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी श्री राजू कातुलकरएश्रीमती संगीत सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्री यशपाल मालवीय ने प्रतिभागियों को भंडारण व्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा मानकों एवं पीडीएस संचालन की विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक गेहूं, चावल, नमक सहित अन्य आवश्यक खाद्यान्न उचित मूल्य पर पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण अत्यंत आवश्यक होता है। युवाओं को सरकारी भंडार गृह में खाद्यान्न

आगमन से लेकर अंतिम वितरण तक की प्रत्येक प्रक्रिया का अवलोकन कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले वाहनों की गेट एंट्री की जाती है, जिसके बाद खाद्यान्न से भरे ट्रकों का वजन किया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता परीक्षण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया अपनाई जाती हैए जिसमें विशेष रूप से गेहूं की गुणवत्ता, नमी, स्वच्छता एवं भंडारण योग्य स्थिति की जांच की जाती है। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि खाद्यान्नों को वैज्ञानिक तरीके से स्टैकिंग कर सुरक्षित रखा जाता है ताकि नमी, फफूंदी एवं कीटों से बचाव हो सके। भंडारण केंद्रों में प्रत्येक सात दिन के अंतराल पर कीटनाशक स्प्रे एवं नियमित निरीक्षण किया जाता हैए जिससे खाद्यान्न सुरक्षित एवं उपयोग योग्य बना रहे। अधिकारियों ने बताया कि रायसेन जिले की पीडीएस दुकानों को यहीं से खाद्यान्न आवंटित किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशन दुकानों तक सामग्री पहुंचाई जाती है। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण प्रणाली से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गंभीरता से समझा तथा अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त की। प्रतिभागियों ने कहा कि इस प्रकार के अनुभवात्मक कार्यक्रम युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने और शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक बनाने में अत्यंत उपयोगी हैं। इस अवसर पर M4 Bharat रायसेन की डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती मोनिका चौधरी तथा युवा समाज सेवी श्री विशाल सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिलता है, जिससे उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक समझ का विकास होता है।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने युवाओं से खाद्य सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जनसेवा से जुड़ी व्यवस्थाओं को समाज तक पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। M4 Bharat द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं को शासन की व्यवस्थाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

शॉर्ट न्यूज

रायसेन जिले की 2,43,683 बहनों के खाते में 35 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित

रायसेन (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश के साथ ही रायसेन जिले की 2,43,683 बहनों के खातों में 35 करोड़ 83 लाख 56 हजार 900 रूपये की राशि अंतरित की।

बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर धारा 136 में होगी कार्रवाई

रायसेन (निप्र)। विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि यदि बिजली के मीटर में अनावश्क छेड़छाड़ पाई जाती है तो ऐसा करने वालों के विरूद्ध धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी। कंपनी का कहना है कि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑन लाइन वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा उपाय यूपीएवाय ऐप या बिजली वितरण केन्द्र, जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण की पुख्ता व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।विद्युत अधिनियम. 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ष्अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइनए सामग्री या मीटर को हटाएगा या अन्यत्र जगह लगाता हैए चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहींए तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

दिव्यांगों को बस किराये में 50 प्रतिशत छूट

सीहोर (निप्र)। राज्य शासन ने प्रदेश की सभी प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिये हैं। दिव्यांग व्यक्ति को यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर यह छूट मिल जायेगी।परिवहन आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं। दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में केन्द्र या राज्य शासन द्वारा जारी यूनीक डिसऐबिलिटीज आई.डी. कार्ड प्रस्तुत करने पर किराये में 50 प्रतिशत छूट का लाभ दें।केन्द्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यूनीक आई.डी. फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज (यूडीआईडी) प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड दिये जा रहे हैं। कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड निर्माण में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है।

फायर सेफ्टी सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

बैतूल (निप्र)।अपर मिशन संचालक भोपाल के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय बैतूल एवं जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में 4 मई से 10 मई तक फायर सेफ्टी सप्ताह अंतर्गत जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला चिकित्सालय बैतूल में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ जगदीश घोरे के निर्देशन में फायर सेफ्टी सप्ताह अंतर्गत 4 मई 2026 को शपथ ग्रहण एवं नर्सिंग छात्राओं को फायर सेफ्टी प्रशिक्षण दिया गया। वहीं 5 मई को जिला बैतूल की क्वालिटी टीम द्वारा संस्था का आंतरिक फायर सेफ्टी मूल्यांकन किया गया। फायर सेफ्टी पोस्टर प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता 7 मई को आयोजित कर प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इसके अलावा 8 एवं 10 मई को अस्पताल में कार्यरत सभी अधिकारियों , कर्मचारियों के लिए जिला होमगार्ड बैतूल एवं फायर सेफ्टी कंसलटेंसी एजेंसी द्वारा फायर सेफ्टी एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। साथ ही फायर सेफ्टी सप्ताह अंतर्गत शपथ ग्रहण एवं जागरूकता गतिविधियां जिले की विभिन्न संस्थाओं में आयोजित की गई। जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में क्वालिटी असेसर कविता सिंह, एमएच कोर्डिनेटर श्रीमती सविता चढ़ोकार, सीनियर नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती शोभा बानखेड़े एवं स्टाफ मौजूद रहा।

सीहोर जिले की 2,40,252 बहनों के खाते में 35 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले की 2,40,252 बहनों के खातों में 35 करोड़ 38 लाख 59 हजार 900 रूपये की राशि अंतरित की।

स्वरोजगार स्थापित करने संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

रायसेन (निप्र)। अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं तथा महिलाओं को लाभान्वित करने 40 इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आवेदक स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से एक लाख रू से 50 लाख रू तक का उद्योग इकाई और सेवा इकाई के लिए एक लाख रू से 25 लाख रू तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना के तहत स्वीकृत इकाई लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान देय होगा। संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष तक की आयु के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

जिले की 271319 लाडली बहनों के खातों में 40 करोड़ रुपये अंतरित

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा आथ बुधवार 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में माह मई 2026 की आर्थिक सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की है। इस अवसर पर विदिशा जिले की 2 लाख 71 हजार 319 लाडली बहनों के खातों में लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की हुई है।

इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण विदिशा के एनआईसी वीसी कक्ष में भी किया गया। यहां कार्यक्रम में उपस्थित विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण व जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया के अलावा हितग्राही लाडली बहनाएं मौजूद रहीं। उपस्थित सभी के द्वारा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांस्बा ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

अंतर्गत विदिशा जिले की पात्र महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ उनके परिवारों को भी आर्थिक मजबूती मिल रही है। जिले के विभिन्न जनपद एवं नगरीय निकायों की लाभार्थी महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इनमें जनपद पंचायत बासौदा की 40,483, ग्यारसपुर की 24,298, कुरवाई की 27,305, लटेरी की 25,547, नटेरन की 33,159, सिरोंज की 36,572 तथा विदिशा की 29,330 महिलाएं शामिल हैं।

वहीं नगरीय निकायों में नगरपालिका गंजबासौदा की 11,949, नगरपालिका सिरोंज की 8,747, नगरपालिका विदिशा की 25,578, नगर परिषद कुरवाई की 2,988, नगर परिषद लटेरी की 3,335 तथा नगर परिषद शमशाबाद की 2,028 महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की जाएगी।

पंजीकृत श्रमिकों के लिए संजीवनी बनीं शासकीय योजनाएं

रायसेन (निप्र)। प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्रम विभाग और विभिन्न बोर्ड्स के माध्यम से अब श्रमिकों को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हर कदम पर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। इनमें प्रसूति सहायता 16 हजार, बेटियों के विवाह के लिये अनुदान 49 हजार रूपये और 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क चिकित्सा लाभ (आयुष्मान भारत) शामिल है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा देने के लिए श्विदेश अध्ययन योजनाश् के तहत 40 हज़ार डॉलर तक की सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही अधिकतम 10 हजार यू.एस. डॉलर प्रतिवर्ष बतौर वार्षिक निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जाता है। राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 हज़ार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्रमिकों के आवास निर्माण के लिए एक लाख रूपये तक, ई-स्कूटर खरीदी के लिए 40 हजार रूपये तक और औजार अनुदान भी सीधे उनके बैंक खातों ष्ठक्चञ्ज में भेजा जा रहा है। पात्र श्रमिक निर्धारित समय-सीमा के भीतर श्श्रम सेवा पोर्टलश् या श्लोक सेवा केंद्रश् के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

ग्रामीणों को इलाज के लिए परेशान न होने पड़े : कलेक्टर डॉ सोनवणे

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को चिचोली विकासखंड के ग्राम चिरापाटला का भ्रमण कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचे और ग्रामीणों को उपचार के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरापाटला में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन एवं गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच संबंधी रजिस्टर और प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। उन्होंने नेत्र जांच एवं अस्थि रोग जांच व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर शिविर संचालन की गुणवत्ता परखी।

उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्र में नियमित एवं सुचारू रूप से डिलेवरी सेवाएं संचालित हों तथा चिकित्सक और स्टाफ केंद्र पर उपस्थित रहें, ताकि ग्रामीणों को समय पर उपचार मिल सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने एंटीवेनम, आयरन सिरप सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि उपलब्ध दवाओं का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग न होने से मरीजों को अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर न लगाना पड़े, जिससे उनकी स्थिति और अधिक गंभीर हो। इस दौरान ग्राम अजई निवासी रमेश कन्हैया ने दिव्यांगता कार्ड नहीं बनने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने मेडिकल बोर्ड के माध्यम से शीघ्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी विकासखंडों में प्रत्येक माह में एक बार मेडिकल बोर्ड आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि दिव्यांगजनों को सुविधा मिल सके। इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम पंचायत चिरापाटला के सभाहॉल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायत एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तीन दिवस के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व से संचालित जल योजनाएं बंद न हों और सभी घरों तक नियमित पानी पहुंचे। निर्माणाधीन सड़क के कारण क्षतिग्रस्त हुई नल-जल योजना के निराकरण के निर्देश भी जनपद सीईओ को दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने स्वीकृत हैंडपंप कार्यों में बिना अनुमति स्थल परिवर्तन पर नाराजगी जताते हुए संबंधितों से वसूली की चेतावनी दी। उन्होंने फौती नामांतरण, अभिलेख दुरुस्ती, राशन कार्ड, पीएम आवास सहित विभिन्न शिकायतों पर त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए तथा पटवारियों को राजस्व प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण करने की सख्त हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ग्रामीणों से ली। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में शून्य पंजीयन पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

कलेक्टर के प्रयासों से विद्यालयों में बढ़ीं सुविधाएं

सीएसआर सहयोग से जिले के 10 शासकीय विद्यालयों को मिला नया फर्नीचर

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में विद्यार्थियों को बेहतर एवं सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रभावी प्रयास कर रहा है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के सतत प्रयासों एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप जिले के शासकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत हुडको एवं बीपीसीएल बीना ऑयल रिफाइनरी के सहयोग से जिले के अनेक विद्यालयों को डबल डेस्क फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है।

इस महत्वपूर्ण पहल के तहत लटेरी विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनारसी कलां, शासकीय हाई स्कूल जावती तथा बासौदा एवं ग्यारसपुर विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल खजूरी और शासकीय हाई स्कूल इंदरवास को प्रत्येक विद्यालय में 50-50 डबल डेस्क फर्नीचर सेट प्रदान किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को बैठने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तथा कक्षाओं में अध्ययन का वातावरण अधिक व्यवस्थित

और अनुकूल बनेगा। इसके अतिरिक्त लटेरी विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरवास, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कालादेव एवं शासकीय माध्यमिक शाला कोलुआ पठार को प्रत्येक विद्यालय में 100-100 डबल डेस्क फर्नीचर सेट उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं विदिशा विकासखंड के शासकीय माध्यमिक शाला स्टेशन एरिया को भी 50 डबल डेस्क फर्नीचर सेट प्रदान किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से जिले के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। नवीन फर्नीचर उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा, जिससे उनकी अध्ययन गतिविधियों में सकारात्मक सुधार आएगा। विद्यालय प्रबंधन समितियों, शिक्षकों एवं स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

बुधनी तहसील में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य हुआ पूरा, एसडीएम और तहसीलदार से पूरी टीम को दी बधाई

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधनी तहसील में मकान सूचीकरण का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बुधनी एसडीएम श्री दिनेश सिंह तोमर और तहसीलदार श्री ललित सोनी ने सभी सुपरवाइजर्स, प्रगणक और पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कम समय में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति न केवल अन्य सुपरवाइजर्स और प्रगणकों के लिए प्रेरणास्रोत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यदि जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य किया जाए तो निर्धारित समयसीमा के भीतर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

जन-कल्याण के लिए जिला प्रशासन व उद्योगपतियों ने मिलाया हाथ

रायसेन (निप्र)। एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मण्डीदीप के सभागार में आज 13 मई को कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में उद्योगपतियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में औद्योगिक समस्याओं के निराकरण और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (ष्टस्क्र) के माध्यम से जन-कल्याणकारी कार्यों को गति देने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। बैठक में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समाधान के लिए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ''भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा'' के

सकारात्मक संदेश को साझा किया। उन्होंने आग्रह किया कि उद्योग जगत भविष्य में गैस, डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए नवाचारी ऊर्जा विकल्पों पर ध्यान दें, जिससे देश ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही ष्टस्क्रमद के माध्यम से सामाजिक सरोकार के कार्य और जिले के विकास में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर जोर दिया। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने शिक्षा, शासकीय स्कूलों में 12वीं कक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना और प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर व वाटर प्यूरीफायर की उपलब्धता, स्वास्थ्य और पोषण तथा अति-कुपोषित बच्चों के लिए 6 ह्त्रष्ट भवनों में ,ष्ट लगाना और आंगनवाड़ी केंद्रों में सोलर सिस्टम की स्थापना। साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में जिले में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण और प्रधानमंत्री आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना रहा। एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज के संरक्षक श्री राजीव अग्रवाल ने कलेक्टर श्री विश्वकर्मा को वर्तमान में चल रहे ष्टस्क्रकार्यों से अवगत कराया और प्रस्तावित जनकल्याणकारी कार्यों हेतु आश्वासन दिया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, एसडीएम गौहरगंज श्री चंद्रशेखर श्रीवास्तव, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री सिद्धार्थ खरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति उपस्थित रहे।

उज्जैन की जनता सिंहस्थ के कार्यों में सहयोग कर पेश कर रही हैं नई मिसाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने हरसिद्धि पाल से रामघाट मार्ग चौड़ीकरण कार्य का किया निरीक्षण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 के लिए श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के आवागमन एवं सुविधाएं बढ़ाने के लिए घाटों एवं मार्गों के चौड़ीकरण कार्य किए जा रहे है। सरकार द्वारा सभी कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। सिंहस्थ के लिये सभी कार्य इस तरीके से किए जा रहे है कि पौराणिक और धार्मिक नगरी उज्जैन को लंबे समय तक उनका लाभ प्राप्त हो। उज्जैन के जनप्रतिनिधि, सभी धर्म के अनुयायी और नागरिक विकास कार्यों का समर्थन कर रहे है और सहयोग प्रदान कर देश के लिए एक नई मिसाल बन रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को उज्जैन में रामघाट पहुंचकर हरसिद्धि पाल से राम घाट मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत कार्य तेजी गति, गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें।

होमगार्ड द्वारा आयोजित बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का अवलोकन किया–मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरसिद्धि पाल से रामघाट मार्ग चौड़ीकरण के निरीक्षण के बाद होमगार्ड द्वारा आयोजित बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होमगार्ड जवानों की हौसला अफजाई की। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री संतोष कुमार जाट ने जानकारी दी कि होमगार्ड द्वारा 250 होमगार्ड जवानों को बाढ़ बचाव के लिए डीप डाइविंग, नाविकों, स्विमिंग, लाइफ जैकेट के उपयोग का तरीका, आपदा और बाढ़ बचाव सामग्री का उचित प्रयोग, अंडर वॉटर रेस्क्यू और सर्फेस वॉटर रेस्क्यू का 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ओंकारेश्वर-ममलेश्वर विकास प्राधिकरण बनेगा

मोहन यादव सरकार जल्दी ही ओंकारेश्वर ममलेश्वर विकास प्राधिकरण बनाएगी। इस विकास प्राधिकरण के जरिए ओंकारेश्वर के विकास को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा पीएचई विभाग के शहरी क्षेत्र के अमले को नगरीय निकायों में मर्ज किए जाने पर भी सरकार जल्द फैसला करेगी। सरकार ने प्रदेश की तीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को भोपाल, उज्जैन, जबलपुर में विभाजित करने का भी फैसला किया है। साथ ही चित्रकूट और ओरछा में पर्यटन विकास के प्रस्ताव मंजूर करने के साथ राम वन गमन पथ के काम में भी तेजी लाने का निर्णय हुआ है।

आदि उत्सव जनजातीय गौरव, संस्कृति और उद्यमिता का है अद्भुत संगम : सीएम यादव

जनजातीय परम्पराओं को किया जा रहा है संरक्षित

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 'आदि उत्सव' जैसे आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विरासत से विकास के संकल्प को पूरा करने का माध्यम भी हैं। जनजातीय संस्कृति से जुड़ी वैभवशाली परम्पराओं के प्रदर्शन और संरक्षण में ऐसे उत्सवों का विशेष महत्व है। पिछले एक दशक से यह आयोजन जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और वैभवशाली विरासत को सहेजने के साथ आधुनिक उद्यमिता के माध्यम से उसे नए आयाम देने का सशक्त मंच बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह उत्सव ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो होली और दीपावली एक साथ आ गई हों। उन्होंने मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, उमरिया और छिंदवाड़ा अंचल से पहुंचे गोंड एवं बैगा समाज के भाई-बहनों का स्वागत करते हुए आयोजन की भव्यता की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंडला जिले में रामनगर में हुए 'आदि उत्सव' को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंडला का गोंड आर्ट, कर्मा, सैला और रीना नृत्य तथा बैगा समाज का परधोनी नृत्य जनजातीय संस्कृति की सुंदर अभिव्यक्ति हैं। इन परंपराओं को संरक्षित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कोदो-कुटकी सहित अन्य मोटे अनाजों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए विशेष अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह उत्सव जनजातीय महापुरुषों और वीर नायकों

बिरसामुंडा, रानी दुर्गावती, टंट्याभील, राजा शंकरशाह, कुंवर रघुनाथशाह, दलपतशाह की शौर्य गाथाओं का स्मरण कराने वाला प्रेरणादायी मंच भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़ने और जनजातीय महापुरुषों के वंशजों का सम्मान करने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। यह आयोजन जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

आदि उत्सव में हुआ है शिल्पियों का संगम– मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गत एक दशक से आदि उत्सव का आयोजन हो रहा है जो प्रशंसनीय है। आदि उत्सव में बैगा ही नहीं गौंड और अन्य जनजातीय बंधु हिस्सा ले रहे हैं। आदि शिल्प में उद्यमियों और शिल्पियों का संगम भी हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजाति बोली और परंपराओं को हमें अगली पीढ़ी तक ले जाना है। जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र भी यहां उपयोग में लाए गए हैं। साथ ही कर्मा सेला, लोक नृत्य की छटा बिखरी है। श्रीअन्न का उत्सव भी मनाया जा रहा है। प्रदेश में कोदो कुटकी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजाति समाज के नायक भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, टंट्या मामा, रघुनाथ शाह, भभूत सिंह आदि के सम्मान के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें ऐसे जनजाति नायकों के जन्म स्थल और कर्म स्थल पर कैबिनेट बैठक और अन्य आयोजन किए गए हैं।

जनजातियों के लिए बढ़ाया है बजट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए 47 हजार 425 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। तेंदूपत्ता संग्रह कार्य का लाभ जनजाति समाज को मिल रहा है। पीएम जनमन और धरती आबा अभियान से जनजातियों का हित संवर्धन हुआ है। वन धन केंद्रों के माध्यम से भी जनजातीय वर्ग लाभान्वित हो रहा है। अधोसंरचना विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। आकांक्षा योजना के क्रियान्वयन और सांदीपनि एवं एकलव्य विद्यालयों से जनजाति समाज के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सिकल सेल जैसे रोगों के नियंत्रण की पहल भी की गई है।

गोंडवाना गौरव को नई पहचान दे रहा 'आदि उत्सव'

केन्द्रीय मंत्री ओरांव

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओरांव ने कहा कि गोंडवाना राजवंश के इस ऐतिहासिक महल का जीर्णोद्धार कराने के बाद वर्ष 2016 से लगातार यह आदि उत्सव आयोजित किया जा रहा है। जनजातीय गौरव को सम्मान देने की पहल सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जब 1999 में उन्होंने पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया। मंडला के इस महल के जीर्णोद्धार के लिए मंत्रालय ने 1.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन, आहार अनुदान, विभिन्न छात्रवृत्तियाँ, जनजातीय बच्चों की उच्च शिक्षा जैसे अनेक काम जनजातीय समाज के कल्याण के लिए किये जा रहे हैं।

आदि उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर बना रहा विशिष्ट पहचान

मंत्री श्रीमती उइके

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके ने कहा कि रामनगर का 'आदि उत्सव' अब केवल क्षेत्रीय आयोजन नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और गौरव के प्रतीक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत गोंडी बोली में करते हुए जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया। आज यह आयोजन एक बड़े उत्सव के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसमें जनजातीय संस्कृति, लोक कला, परंपराओं और इतिहास का भव्य प्रदर्शन किया जा रहा है।

उत्सव भावी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम

सांसद कुलस्ते

सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि यह आयोजन जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आज तक राज परिवार, पंडा, पुजारी एवं भूमका समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों से आए विभिन्न राज परिवार के सदस्य, जनजातीय गौरव की जानी-मानी हस्तियाँ सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनजातीय वर्ग के लोग भी मौजूद रहे।

मंदिर है भोजशाला, फैसले के बाद रोने लगे हिंदू याचिकाकर्ता

किन सबूतों ने हिंदुओं का पक्ष किया मजबूत

धार (नप्र)। हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पूरा मंदिर है। साक्ष्यों के आधार पर पूरा क्षेत्र हिंदू मंदिर है। मुसलमानों से कहा है कि कलेक्टर से मिलकर अपने लिए अन्य स्थान चिह्नित करें। केंद्र को आदेश दिया है कि लंदन से लाकर वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करें। गोपाल शर्मा ने कहा कि यह मंदिर था और मंदिर है। यह फैसला उनलोगों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इसके लिए शहादत दी है। इसके बाद गोपाल शर्मा भावुक हो गए।

भावुक हो गए याचिकाकर्ता

वहीं, याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा अपनी बात कहते-कहते भावुक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सालों की तपस्या का फल है। हिंदू संगठन के लोग भोजशाला परिसर में आज से ही नियमित पूजा की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी एएसआई को है। मुस्लिम पक्ष का दावा पूरी तरह से खारिज हो गया है। इस फैसले के बाद हाईकोर्ट के बाहर जश्न का माहौल था।

700 साल पुराने प्रकरण का अंत

अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने 700 साल पुराने प्रकरण को विराम दिया है। साथ ही यह तय किया है कि भोजशाला एक मंदिर है। राजा भोज द्वारा स्थापित यह एक मंदिर है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भोजशाला एक मंदिर है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो साक्ष्य रखे गए हैं, इसके बाद न्यायालय ने तय किया है कि यह एक सरस्वती मां का मंदिर है। एएसआई की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट हो गया है कि यह मंदिर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसे हिंदुओं को सौंपा जाए। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वे लोग चाहें तो सरकार को आवेदन दे सकते हैं। सरकार उनके आवेदन पर विचार करेगी कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए कोई अलग जगह दी जाए या न दी जाए। माननीय न्यायालय ने लंदन से मूर्ति वापस लाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार आगे कदम उठाएगी।

ये सबूत रहे अहम

एडवोकेट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट से यह साफ था कि इमारत 11वीं सदी की बनी है। हवनकुंड भी ईंटों का बना हुआ है। ईंटें भी 11वीं सदी की हैं। इमारत का स्वरूप मंदिरों के रूप में हैं। अब यह तय हो गया है कि यह मंदिर है। ऐसे में यहां नियमित रूप से पूजा होगी। अब यहां किसी प्रकार की नमाज नहीं होगी। सिर्फ हिंदू पद्धति से पूजा होगी।

सच की जीत हुई है- हिन्दू समाज– कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर का धार्मिक स्वरूप तय कर दिया है। वहीं, इस फैसले के बाद धार में जश्न का माहौल है। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि सच की जीत हुई है।

पुलिस सुरक्षा के बीच नमाज के थोड़ी देर बाद आया हाईकोर्ट का फैसला

भोजशाला परिसर में अब नहीं होगी जुमे की नमाज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया है। शुक्रवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने

फैसला सुनाया है। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर पर नमाज की इजाजत दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब यहां जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी।

जय श्रीराम के नारे, हाथों में ध्वज, जमकर बांटी मिठाई

भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला आते ही जश्न शुरू हो गया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भोजशाला परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोगों ने एक दूसरे को मिठाई और लड्डू खिलाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हिन्दू पक्ष के जश्न को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था कड़ी कर दी है। धार के हर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

ध्वज लेकर निकले लोग– हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में पताका और ध्वज लेकर मंदिर परिसर के बाहर जमा हो गए हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल, भोजशाला के मेन गेट पर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

भोजशाला के 188 स्तंभों की 'मौन गवाही' बनी सबसे बड़ा सबूत

धार की भोजशाला को हिन्दू मंदिर मानते हुए इंदौर हाईकोर्ट के अहम फैसले में एएसआई की रिपोर्ट सबसे अहम रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट को आधार मानकर ही कोर्ट ने भोजशाला विवाद को मंदिर करार दिया है। बता दें कि फैसले में अहम कड़ी बनकर सामने आई रिपोर्ट में भोजशाला परिसर के वो 188 मूल आधार स्तंभ जिनमें 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्धस्तंभों फैसले का मुख्य आधार बने, जिन पर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक, देवी-देवताओं की आकृतियां और मंदिर शैली की नक्काशी मिलने का दावा किया गया। इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।

मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद में एएसआई की 2024 सर्वे रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। रिपोर्ट के अनुसार परिसर में कुल 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्धस्तंभ मौजूद हैं। इनमें से कई स्तंभों पर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह, देवी-देवताओं की आकृतियां और पारंपरिक मंदिर शैली की नक्काशी पाई गई।

स्तंभों पर क्या वास्तुकला मिली थी ?

एएसआई रिपोर्ट में कहा गया कि इन स्तंभों पर कीर्तिमुख, नागबंध और अन्य प्राचीन मंदिर वास्तुकला से जुड़े डिजाइन बने हुए हैं। साथ ही कई स्तंभों पर मानव और पशुओं की आकृतियां भी मिलीं, जिन्हें बाद में क्षतिग्रस्त किए जाने के संकेत मिले हैं। एएसआई रिपोर्ट के अनुसार, करीब 1265 ईस्वी में मस्जिद निर्माण के दौरान पुराने हिंदू मंदिरों के स्तंभों और मलबे का पुनः उपयोग किया गया था। यही तथ्य हिंदू पक्ष की दलीलों का बड़ा आधार बने। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कई स्तंभों पर भगवान गणेश ब्रह्मा, नृसिंह और भैरव जैसी मूर्तियों की नक्काशी दिखाई दी, जिन्हें हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का प्रमुख प्रमाण बताया।

महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए फैसला सुनाया

हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए फैसला सुनाया। फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने खुशी जताई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

भोजशाला पर एएसआई रिपोर्ट की मुख्य बातें

● एएसआई सर्वे रिपोर्ट में बनी भोजशाला फैसले का मुख्य आधार ● रिपोर्ट में भोजशाला में 188 आधार स्तंभों का उल्लेख ● परिसर में 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्धस्तंभ मौजूद हैं ● कई स्तंभों पर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह और नक्काशी पाई गई ● स्तंभों पर कीर्तिमुख, नागबंध और पारंपरिक मंदिर शैली की आकृतियां मिलीं ● रिपोर्ट में दावा, मस्जिद निर्माण में पुराने मंदिर के स्तंभों और मलबे का पुनः उपयोग ● कई पिलर पर गणेश नृसिंह और भैरव जैसी मूर्तियों की नक्काशी मिली ● सर्वे के दौरान मानव और पशुओं की आकृतियां भी मिलीं, जिन्हें क्षतिग्रस्त बताया गया

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी जिन्होंने 700 साल पुराने भोजशाला विवाद पर सुनाया फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला पर अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को दोपहर ढाई बजे फैसला पढ़ना शुरू किया था।

जस्टिस विजय शुक्ला– जस्टिस विजय शुक्ला का जन्म 28 जून 1964 को हुआ था। उन्होंने 27 सालों तक एमपी हाईकोर्ट में वकालत की है। 27 मार्च 1987 में वह बार काउंसिल के सदस्य बने थे। 1994 से 1998 तक सरकारी अधिवक्ता के रूप में और 2007 से 2009 तक उप महाधिवक्ता के रूप में काम किया है। वहीं, 13 अक्टूबर 2016 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 17 मार्च 2018 को स्थानीय न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है।

जस्टिस आलोक अवस्थी – जस्टिस आलोक अवस्थी का जन्म 23 अक्टूबर 1969 को हुआ है। वह 30 जुलाई 2025 को एमपी हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं। 22 अक्टूबर 2031 को रिटायर हो जाएंगे। वह लोअर कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे हैं।